A Daily News Magazine

भोपाल

शनिवार, 09 मई, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 246, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

प्रसंगवश

क्या ममता बनर्जी अपनी सियासी जमीन वापस हासिल कर पाएंगी?

रुपसा सेनगुप्ता

भारत की राजनीति ने कई प्रभावशाली महिला नेताओं को देखा है। इस सूची में तीन महिलाओं जे. जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी का ज़िक्र भी ज़रूरी है, जो क्षेत्रीय ताक़त से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में रहीं और उन्होंने राजनीति को दिशा दी। दृढ़ता, सशक्त नेतृत्व और मतदाताओं के साथ मज़बूत जुड़ाव के बल पर, वे राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजनीति का निर्णायक चेहरा बन गईं।

उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक अखाड़े में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिस पर लंबे समय से पुरुषों का वर्चस्व रहा था। साल 2016 में जयललिता के निधन और हाल के वर्षों में मायावती के वर्चस्व के कमज़ोर पड़ने के साथ, ममता बनर्जी को एकमात्र कद्दावर महिला नेता माना जाने लगा था। उन्होंने अपने दम पर अपनी पार्टी खड़ी की और उसे सफलता दिलाई। हालाँकि, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मिली ताजा हार के बाद, यह सवाल बना हुआ है कि क्या भारत की इन 'आखिरी महिला योद्धाओं' का अध्याय अब समाप्त हो गया है?

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 207 सीटों के साथ एक ज़बरदस्त जीत हासिल की है। जबकि ममता बनर्जी अपनी सीट भी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। इस चुनाव परिणाम ने भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप पर बहस को फिर से तेज़ कर दिया है। ख़ासतौर पर ममता बनर्जी के घटते प्रभाव को लेकर, जो वाम मोर्चा के 34 साल लंबे शासन को समाप्त कर साल 2011 में बंगाल में सत्ता में आई थीं। हालाँकि, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

भारतीय राजनीति के बड़े फलक पर, कई महिला नेताओं ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इनमें क्षेत्रीय स्तर पर तीन नाम ख़ास तौर पर उभरकर सामने आते हैं- जे जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी। ये सभी अलग-अलग पृष्ठभूमि से आई थीं और इन्होंने अपने-अपने राज्यों में मज़बूत नेतृत्व का आधार तैयार किया। आखिरकार इन्हें क्षेत्रीय स्तर पर ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली और राष्ट्रीय राजनीति में भी इनकी अहमियत बढ़ी। मेदक्षिण भारतीय फ़िल्मों की एक मशहूर अदाकारा से लेकर एक लोकप्रिय राजनेता बनने तक जयललिता का सफ़र बेहद शानदार रहा। वह चार बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनीं, और उनके समर्थकों के बीच उन्हें प्यार से 'अम्मा' कहा जाने लगा। सख्त शासन और जन-कल्याणकारी नीतियों के लिए मशहूर जयललिता ने ज़मीनी स्तर पर लोगों से मज़बूत जुड़ाव बनाया। साल 2016 में उनका निधन हो गया। मायावती, जो भारत की दलित राजनीति का एक अहम चेहरा हैं, एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उत्तर प्रदेश की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनीं। बसपा सुप्रीमो मायावती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। पहचान-आधारित राजनीति और मतदाताओं के बीच उनकी मज़बूत पकड़ ही उनके प्रभाव का मुख्य आधार रही।

समर्थकों के बीच 'दीदी' के नाम से मशहूर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बनाई है।

मज़बूत क्षेत्रीय नेतृत्व, राजनीतिक सफर और शासन शैली के मामले में जयललिता और मायावती से ममता बनर्जी की कुछ समानताएँ हैं, लेकिन उनमें कुछ अहम अंतर भी नज़र आते हैं। जे. जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी ने अपनी-अपनी पार्टियों को ऐसी राजनीतिक ताक़तों में बदल दिया जो पूरी तरह से उनकी अपनी शख्सियत पर आधारित थी। इससे वे अपनी-अपनी पार्टियों का सबसे अहम चेहरा बन गईं। उन्होंने पुरुषों के दबदबे वाली राजनीतिक संस्कृति में अपने लिए जगह बनाई। इसके लिए उन्होंने ज़मीनी स्तर पर मज़बूत नेटवर्क बनाए, लोगों को लुभाने वाले जन-कल्याण के एजेंडे अपनाए और ज़ोरदार राजनीतिक संदेश दिए। लेकिन ममता बनर्जी का कोई राजनीतिक 'गॉडफ़ादर' नहीं था। ममता बनर्जी की सफलता का आधार ज़्यादातर आंदोलन-आधारित राजनीति और लोगों को लुभाने वाली जन-कल्याणकारी योजनाएँ थीं।

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉक्टर उमेश कुमार कहते हैं,'जे जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी के नेतृत्व ने निस्संदेह भारतीय राजनीति के मायने और तौर-तरीके बदल दिए हैं। उनका महत्व सिर्फ़ महिला नेताओं के तौर पर उनकी मौजूदगी में ही नहीं है, बल्कि इस बात में भी है कि उन्होंने पार्टी बनाने, चुनाव प्रचार करने और शासन चलाने की अपनी ख़ास रणनीतियों के ज़रिए महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को किस तरह संस्थागत रूप दिया। उन्होंने मज़बूत राजनीतिक संगठन बनाकर, पुरानी और मज़बूत विपक्षी पार्टियों के खिलाफ़ चुनाव जीतकर, और लोगों को पसंद आने वाली जन-कल्याण की योजनाएँ लागू करके भारतीय राजनीति के उस स्वरूप को चुनौती दी है जिसमें ऐतिहासिक रूप से पुरुषों का ही दबदबा रहा है। ऐसा उन्होंने उन तरीकों से किया है जो पहले कभी नहीं देखे गए।'

ममता बनर्जी का जुझारू अंदाज़, ज़मीनी स्तर से गहरा जुड़ाव और उनकी सादगी भरी जीवनशैली की छवि उनके पक्ष में बहुत मज़बूती से काम आई। लेकिन हाल के कुछ सालों में उन्हें कुछ झटके भी लगे हैं। तो क्या ममता बनर्जी को हालिया चुनाव में मिली हार उनके राजनीतिक करियर के अंत का संकेत है?

कोलकाता के सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंसेज़ के प्रोफ़ेसर मैदुल इस्लाम ने कहा कि चुनाव में हार का सामना करने के बाद मायावती फिर से उभर नहीं पाई हैं। अब देखना यह है कि ममता के मामले में क्या होता है।' दिल्ली के राजनीतिक अर्थशास्त्री डॉक्टर रोहित ज्योतिष ने कहा कि ममता बनर्जी के मामले में जो बदलाव आया है, वह उस मुक़ाबले की बनावट है, जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक रूप से, पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत ज़्यादा स्थानीय नेटवर्क पर निर्भर थीं। अब संतुलन बदल गया है। हम उस संतुलन में एक तरह की उथल-पुथल देख रहे हैं। अब क्षेत्रीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित चुनौती देने वाले उभर रहे हैं, जिससे मुक़ाबला कहीं ज़्यादा खुला और मुश्किल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ममता की हार कोई निजी पतन है।'

दूसरी ओर, डॉ. कुमार कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब उसका ज़ोर स्थानीय स्तर के प्रचार, चुनावी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देने और बूथ-स्तर के बेहतर प्रबंधन पर है।

मैदुल इस्लाम कहते हैं कि 'साल 2004-2006 में मिली असफलताओं के बाद, कई लोगों ने उनके राजनीतिक कॅरियर का अंत मान लिया था। लेकिन 2006 के बाद, उन्होंने सिंगूर-नंदीग्राम आंदोलन के ज़रिए राजनीति में ज़ोरदार वापसी की। अब वही ममता 2026 में फिर से हार गई हैं। अब वह इस समय का उपयोग कैसे करती हैं, क्या वह अपने संगठन के आधार को फिर से मज़बूत करती हैं, राजनीति से कुछ समय का ब्रेक लेती हैं, या फिर से वापसी करती हैं।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

लाखों, करोड़ों या अरबों नहीं
काल के अनंत प्रवाह से
दर्ज है तुम्हारे भीतर
घटनाएं, क्रम और जीवन
मैं जानता हूं मेरी पृथ्वी
तुम केवल घूमती नहीं
बल्कि देखती भी हो
घटा, बीता और रीता समय
दर्ज करती हो मेरा, हमारा और
अनंत जीवन का सार
मेरी वसुंधरा
तुम पर रहता नहीं इन दिनों
महसूस करता हूं तुम्हें
खुद के भीतर
समझने से परे
और इतिहास बन जाने से पहले.!

– सारंग उपाध्याय

शुभेंदु होंगे बंगाल के नए 'अधिकारी'

- चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता

आज लेंगे बंगाल के सीएम पद की शपथ

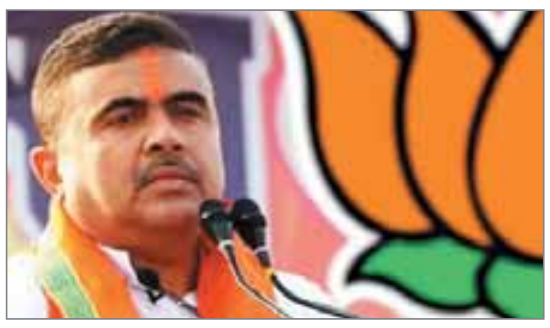

कोलकाता (एजेंसी)। बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। शुक्रवार को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के सीएम मोहन माझी को मौजूदगी में उनके नाम का ऐलान किया है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम और भवानीपुर से जीते हैं। उन्होंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने शुभेन्दु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखा। जिसे विधायकों ने आम सहमति से मुहर लगाई।

तीन दशक बाद संभालेंगे सीएम का पद

शुभेन्दु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर, 1970 को हुआ था। शुभेन्द अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। शुभेन्दु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली है। उन्होंने पंचयत से लेकर पार्लियामेंट तक सफर तय किया। वह 2005 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2009 और फिर 2014 में तामलुक से लोकसभा के सदस्य चुने गए। नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन में उनकी भूमिका ने उन्हें मेदिनीपुर का बादशाह बना दिया।

कांग्रेस से की थी राजनीति की शुरुआत

शुभेन्दु अधिकारी ने राजनीतिक की शुरुआत की थी। वह 1995 में कांग्रेस से कंटई नगर पालिका के पार्षद चुने गए थे। ऐसे में उन्होंने 1995 से 2026 तक करीब तीन दशक बाद मुख्यमंत्री का पद हासिल किया है। शुभेन्दु अधिकारी के परिवार में दो भाई हैं। दिब्येंदु अधिकारी तामलुक से सांसद और विधायक रह चुके हैं। दूसरे भाई सौमेंद्र अधिकारी कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह वर्तमान में कांथी से सासंद हैं। शुभेन्दु अधिकारी अविवाहित हैं। हैं। शुभेन्दु अधिकारी की मां का नाम गायत्री अधिकारी है। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए समर्पित कर रखा है। शुभेन्दु अधिकारी शनिवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे।

सांस्कृतिक धरोहर भावी पीढ़ियों को समृद्ध अतीत से जोड़ने का सशक्त माध्यम : मुख्यमंत्री

प्राचीन मंदिरों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार से सशक्त हो रहा सांस्कृतिक वैभव

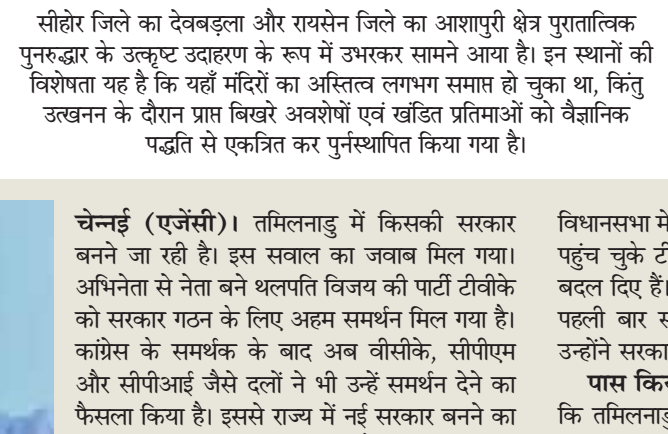

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरें भावी पीढ़ियों को समृद्ध अतीत से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। साथ ही हमारे गौरवशाली इतिहास, ज्ञान, कला और सभ्यता की जीवंत प्रतीक हैं। इन धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन समय की आवश्यकता है, जिससे भावी पीढ़ियाँ भी अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व का अनुभव कर सकें। राज्य सरकार 'विरासत भी-विकास भी' के संकल्प को साकार करते हुए सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में प्राचीन मंदिरों एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य निरंतर किया जा रहा है। इन प्रयासों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन स्थापत्य कला और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण देश में विशिष्ट पहचान रखता है। संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा प्रदेश में बिखरे मंदिर अवशेषों का वैज्ञानिक पद्धति से मूल स्वरूप में पुर्नस्थापन किया जा रहा है। 'पुनर्सरंचना' एवं 'एनास्टाइलोसिस' जैसी तकनीकों के माध्यम से धरोहरों की मौलिकता और ऐतिहासिकता को संरक्षित किया जा रहा है।

देवबड़ला और आशापुरी बने पुरातात्विक पुनरुद्धार के उत्कृष्ट उदाहरण

सीहोर जिले का देवबड़ला और रायसेन जिले का आशापुरी क्षेत्र पुरातात्विक पुनरुद्धार के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभरकर सामने आया है। इन स्थानों की विशेषता यह है कि यहाँ मंदिरों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था, किंतु उत्खनन के दौरान प्राप्त बिखरे अवशेषों एवं खंडित प्रतिमाओं को वैज्ञानिक पद्धति से एकत्रित कर पुर्नस्थापित किया गया है।

देवबड़ला में परमारकालीन मंदिरों का किया जा रहा है पुर्नस्थापन

घने जंगलों के मध्य स्थित सीहोर जिले के देवबड़ला में 11वीं शताब्दी के परमारकालीन मंदिर अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्निर्माण कराया गया है। यहाँ 'भूमिज शैली' में निर्मित मंदिरों की 'पंच-रथ' योजना तत्कालीन उन्नत स्थापत्य कला का नमूना है। मंदिर क्रमांक-1 एवं 2 के पुनर्सरंचना कार्य में मूल पत्थरों का उपयोग कर उनकी प्राचीनता को सुरक्षित रखा गया है। द्वार-शाखाओं पर उकेरी गई गंगा-यमुना की प्रतिमाएँ तथा सूक्ष्म नक्काशी इस स्थल को विशेष बनाती हैं।

आशापुरी में किया जा रहा है प्रतिहारकालीन मंदिरों का संरक्षण

रायसेन जिले का आशापुरी क्षेत्र अपने प्राचीन मंदिर समूहों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 9वीं शताब्दी के प्रतिहारकालीन मंदिर क्रमांक-17 का पुनरुद्धार किया गया है। मंदिर के वर्गाकार गर्भगृह एवं मुखमंडप को अत्यंत सावधानीपूर्वक पुर्नस्थापित किया गया है। स्थल से प्राप्त शिव-नटेश, लक्ष्मी-नारायण तथा गजासुर संहारक शिव की प्रतिमाएँ प्रदेश की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

तमिलनाडु में रास्ता साफ विजय बनाएंगे सरकार

- वीसीके, सीपीएम, सीपीआई ने किया टीवीके-कांग्रेस गठबंधन का समर्थन

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में किसकी सरकार बनने जा रही है। इस सवाल का जवाब मिल गया। अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके को सरकार गठन के लिए अहम समर्थन मिल गया है। कांग्रेस के समर्थक के बाद अब वीसीके, सीपीएम और सीपीआई जैसे दलों ने भी उन्हें समर्थन देने का फैसला किया है। इससे राज्य में नई सरकार बनने का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े के करीब पहुंच चुके टीवीके गठबंधन ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। विपक्षी दलों के समर्थन के बाद विजय पहली बार सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए हैं और उन्होंने सरकार गठन का दावा पेश कर दिया है।

पास किया 118 का जादुई आंकड़ा- बता दें कि तमिलनाडु में अब टीवीके चीफ थलपति विजय की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है।

माता-पिता खुद तय करेंगे अब स्कूल का बजट और विकास

- खुद बनाएंगे तीन साल का मास्टर प्लान, केंद्र के 15 लाख स्कूलों में बदलाव होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए मई 2026 से नई गाइडलाइन्स लागू करने का निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक बदलाव के तहत देश के लगभग 15 लाख स्कूलों का प्रबंधन अब सीधे तौर पर अभिभावकों के हाथों में होगा। नए नियमों के मुताबिक, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) को 30 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य बिना पीडब्ल्यूडी की मंजूरी के खुद कराने की वित्तीय शक्ति दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इन सुधारों को नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) 2009 के तहत अंतिम रूप दिया है, जिससे अब स्कूल केवल सरकारी संस्थान न रहकर 'सामुदायिक संपत्ति' के रूप में विकसित होंगे। इस व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव 'चेकबुक पावर' में है। अब स्कूल का बैंक खाता हेडमास्टर और एसएमसी अध्यक्ष का होगा।

सालाना 'सोशल ऑडिट' अनिवार्य

व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अब सरकारी ऑडिट के साथ-साथ सालाना 'सोशल ऑडिट' अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें स्कूल के पाई-पाई का हिसाब सार्वजनिक रूप से नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा। 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सीधे कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया।

केसी वेणुगोपाल का केरल सीएम बनना तय!

- राहुल गांधी के हैं खास, एआईसीसी पर्यवेक्षकों को दी अपनी राय

तिरुवनन्तपुरम (एजेंसी)। केरल का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल का जवाब अभी तक कांग्रेस नहीं दे पाई है। हालांकि सूत्रों की मानें तो केसी वेणुगोपाल ही केरल के अगले सीएम होंगे। वेणुगोपाल अभी अलाप्पुझा से सांसद हैं और अभी कांग्रेस के महासचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। अपनी संगठनात्मक काबिलियत के लिए मशहूर वेणुगोपाल ने हाल के सालों में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है, जिसका असर आखिरी फैसले पर पड़ सकता है।

63 में से 47 विधायक केसी वेणुगोपाल के साथ

पार्टी सूत्रों के अनुसार महासचिव केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को एसीसी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ हुई बैठकों में कांग्रेस के 63 निर्वाचित विधायकों में से 47 ने वेणुगोपाल के नाम का समर्थन किया। इनमें सन्नी जोसेफ भी शामिल हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 09 मई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

नई कैबिनेट बनते ही बिहार में बवाल

पटना में टीआरई-4 अभ्यर्थियों पर हुआ लाठीचार्ज

● परीक्षा नियमावली में बदलाव के विरोध में प्रदर्शन

पटना (एजेंसी)। बिहार में बीपीएससी टीआरई-4 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध शुक्रवार को टूट गया। इसके बाद पटना के जेपी गोलंबर पर पुलिस की लाठी से उनका सामना हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। नई कैबिनेट के शपथ लेने के 24 घंटे बाद ही टीआरई-4 के अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। पटना कॉलेज परिसर में हजारों की संख्या में जुटे अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध मार्च निकाला। छात्रों का मुख्य आरोप है कि आयोग ने अप्रैल के मध्य में विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन मई बीतने को है और अब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है। ये प्रदर्शन बाकरगंज और मछुआ टोली होते हुए आगे बढ़ा। स्थिति को देखते हुए पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद मुस्तैद दिखे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इंतजाम दिखा।

टीआरई-4 के विज्ञापन में देरी से छात्र नाराज

अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने 16 अप्रैल को एक पॉडकास्ट के माध्यम से तीन-चार दिनों के भीतर विज्ञापन जारी करने का दावा किया था। आज 8 मई बीत जाने के बाद भी पोर्टल पर कोई अपडेट नहीं है। लगभग 46,595 पदों पर होने वाली इस बहाली को लेकर छात्रों ने सरकार पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। हालांकि, बिहार के नव नियुक्त शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि टीआरई-4 की वैकेंसी बिल्कुल नहीं फंसेगी, उसे लेकर बैठक चल रही है। जल्द ही फैसला लिया जाएगा। लाठीचार्ज के बाद भी बेरोजगार युवक और युवतियों की भीड़ डटी है। एसडीएम रितिका मिश्रा और सिटी मजिस्ट्रेट आदित्य श्रीवास्तव कह रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के लिए आगे आए। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि बिना छात्र नेता दिलीप कुमार के बात नहीं हो सकती। दिलीप कुमार पुलिस के कब्जे में हैं, जिस वजह से गतिरोध और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

एक ही परीक्षा की कर रहे हैं मांग

प्रदर्शनकारी एक तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टीआरई 4 बहाली का नोटिफिकेशन तत्काल जारी करने की मांग कर रहे हैं। आयोग के अधिकारियों ने अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने और सितंबर के अंत में परीक्षा होने की जानकारी दी थी लेकिन मई का दूसरा सप्ताह निकल रहा है और अधिसूचना जारी नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों के बीच गुस्सा इस चर्चा से भी है कि अब बीपीएससी दो चरण में यह परीक्षा लेगा। पहले प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स परीक्षा होगी और फिर उसमें चयनित कैंडीडेट को मुख्य परीक्षा यानी मेन्स में बैठना होगा। आंदोलनकारी पहले की तरह एक ही परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका ने सीजफायर तोड़ ईरान पर फिर की बमबारी

ट्रम्प बोले-डील नहीं की तो और हमले करेंगे, होर्मुज में 1500 जहाज फंसे

तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर बमबारी की है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीजफायर के बीच यह कार्रवाई की। दरअसल, अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस के मुताबिक खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेना ने जास्क के पास ईरानी समुद्री इलाके से होर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर तेहरान डील नहीं करता तो हम फिर हमले करेंगे।

30 दिन के अस्थायी समझौते पर बातचीत

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान 30 दिन तक लड़ाई रोकने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। इसी दौरान स्थायी डील पर बातचीत जारी रहेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि होर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी जंगी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, लेकिन सेना ने उन्हें मार दिया।

दो वर्ष पहले ही 'उदन्त मार्तण्ड' ने तय कर दिया था पत्रकारिता का नैरेटिव : मिथिलेशनन्दिनीशरणजी

भोपाल। पंडित युगलकिशोर शुक्ल जी ने 200 वर्ष पहले एक ही पंक्ति 'हिंदुस्तानियों के हित के हेत' लिखकर सदियों के लिए पत्रकारिता का नैरेटिव तय कर दिया था। यह विचार हनुमत निवास, अयोध्या के आचार्य मिथिलेशनन्दिनीशरण ने व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के संस्थान हैं, लेकिन मनुष्य बनाने के संस्थान कहाँ हैं? यह संस्थान परिवार थे, जिसे हमने कमजोर कर दिया है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के प्रसंग पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की संयुक्त पहल पर आयोजित तीन दिवसीय समारोह 'प्रणाम उदन्त मार्तण्ड' का आयोजन भारत भवन में किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष सत्र 'उत्तिष्ठ भारत' में आचार्य मिथिलेशनन्दिनीशरण ने अपना पाथेय प्रदान किया और उपस्थित विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।

इस अवसर पर आचार्य मिथिलेशनन्दिनीशरण जी ने कहा कि मनुष्य निर्माण की सबसे मजबूत प्रयोगशाला परिवार है। आज यह प्रयोगशाला कुछ शिथिल हुई है। परस्पर विश्वास और संवाद कम हो गया है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने लिए कुछ नहीं सीखा है बल्कि बाजार में बेचने के लिए अपने को तैयार किया है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं ने हमें तैयार किया है, बाजार ने उनके प्रति अविश्वास का भाव पैदा कर दिया है। इसके लिए तर्क दिया है कि जीवन मूल्यों में यह कमी जेनरेशन गैप के कारण है। जबकि जेनरेशन गैप जैसा कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा है भी तो क्या इस गैप को भरने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आचार्य ने कहा कि एक भ्रांति आई है कि सफलता पाने के लिए सिद्धांतों के मार्ग को छोड़ना पड़ता था। इस भ्रांति से बाहर निकलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सही-गलत होने से या तर्कों से परिवार नहीं चलता है। संबंध निभाने के भाव से ही परिवार चलते हैं। इसी में मनुष्यत्व का निर्माण होता है।

उन्होंने आग्रह किया कि हमें फिल्मों और सीरियल से अपने धर्म को, ग्रंथों को और कहानियों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को समझने के लिए हमें मूल ग्रंथ पढ़ने चाहिए। युवा को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा होने का है अपनी आग

को संभालने की शक्ति आ जाना।

इस अवसर पर वरिष्ठ संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि अक्षर ब्रह्म होता है और उस अक्षर से जो शब्द निर्मित होता है परब्रह्म होता है। जो अक्षर और शब्द की साधना करता है, वे ब्रह्मर्षि और महर्षि होते हैं। वहीं, वरिष्ठ संपादक राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने 'उत्तिष्ठ भारत' का आह्वान सोए हुए भारत को जगाने के लिए किया। स्वामी विदेश में हिन्दू धर्म का डंका बजाने के लिए गए और कहा कि गर्व से कहो हम हिन्दू हैं। जब वे भारत लौट तो भारत की माटी को अपने माथे से लगाया। इस सत्र का संचालन वरिष्ठ पत्रकार शिफाली पांडेय ने किया।

पत्रकारिता जगत का सूर्य है 'उदन्त मार्तण्ड

अयोध्या के हनुमत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनीशरण ने कहा कि दो शताब्दी पहले एक मनीषी ने एक चिंता व्यक्त की उसका प्रतीक है उदन्त मार्तण्ड। उनके मन में आया कि हमारे संवाद बाहरी भाषा में क्यों हो, मातृभाषा में क्यों नहीं? अपनी भाषा और उससे बनते संवाद में पंडित युगलकिशोर शुक्ल ने 'हिंदुस्तानियों के हित के हेत' के रूप में कियाद्य

उन्होंने 'उदन्त मार्तण्ड' शीर्षक को स्पष्ट करते हुए बताया कि 'उदन्त' यानी समाचार और 'मार्तण्ड' यानी सूर्य। नैरेटिव की शक्ति पर आचार्य ने कहा कि शुक्ल जी ने पहली ही पंक्ति में 'हिंदुस्तानियों के हित के हित' लिखकर सदियों के लिए पत्रकारिता का नैरेटिव तय कर दिया था।

आचार्य जी ने कहा कि पत्रकारिता समाज की सेवा में नियुक्त व्यवस्था है। पत्रकारिता सत्ता या विपक्ष का झंडा उठाने के लिए नहीं है। पत्रकारिता का दायित्व सत्व की रक्षा करना और उसे ही व्यक्त करना है।

एआई और डीप फेक स्वर्ण मृग हैं, इनसे सावधान रहें : कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के इस प्रसंग पर हम पंडित युगलकिशोर शुक्ल और हिंदी पत्रकारिता को याद करेंगे।

कुलगुरु ने आधुनिक तकनीक और पत्रकारिता के सामने मौजूद खतरों पर गंभीर बात की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक को 'स्वर्ण मृग' (मायावी सोने का हिरण) बताया। यदि छात्र इस मायावी जाल में फँसे, तो वे त्रेता युग में नहीं हैं जहाँ सुखांत होगा बल्कि कलयुग में है जहां एक गलती से 'वनवास' में 14 साल कोर्ट-कचहरी और मानहानि के चक्करों में बीत जाएँगे।

मिशनरी जर्नलिज्म बनाम 'नेशन फर्स्ट': – **उदय माहुरकर**– भारत सरकार के पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने पत्रकारिता के इतिहास और वर्तमान ध्रुवीकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता से पहले पत्रकारिता एक 'मिशन' थी। आज के दौर में पत्रकार को लेफ्ट या राइट की विचारधारा से ऊपर उठकर 'नेशन फर्स्ट' (राष्ट्र प्रथम) के सिद्धांत पर सत्य को प्रदर्शित करना चाहिए।

राम कार्य की दृष्टि से हिंदी की सेवा करें : लेखक एवं प्राध्यापक डॉ. सी. जयशंकर बाबू ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्ष की यात्रा में, दक्षिण भारत में हिंदी पत्रकारिता के 130 वर्ष की साझेदारी है। हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ गैर-हिंदी भाषी क्षेत्र से हुआ है। इसी प्रकार, भारतीय हिंदी साहित्य का शुभारंभ दक्षिण भारत से हुआ है। इतिहास के पुनर्लेखन में यह बात प्रमुखता से दर्ज होनी चाहिए। तमिल के पत्रकार सुब्रमण्यम भारती ने 1906 में तमिल समाचार पत्र में हिंदी के समाचारों को शामिल किया। दक्षिण में हिंदी की चेतना को देखना है तब आपको 18वीं सदी के केरल के श्रीराम वर्मा का नाम याद रखना होगा। राम कार्य को करने की जो दृष्टि चाहिए, उसी चेतना के साथ दक्षिण भारत में हिंदी की सेवा की जाती है। कहा जाता है कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध है लेकिन कोई यह नहीं बताता कि 1950 के दशक में तमिलनाडु सरकार का हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था।

डिजिटल समय में टीवी पत्रकारिता : वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण दुबे, बृजेश राजपूत, सलमान रावी, दीप्ति चौरसिया, सुधीर दीक्षित और अनुराग द्वारी ने 'डिजिटल समय में टीवी पत्रकारिता' पर अपने विचार साझा किए और विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। सबने माना कि डिजिटल दौर में टीवी पत्रकारिता के सामने चुनौतियां तो आई हैं लेकिन लोग अभी भी टीवी के प्रति आकर्षित हैं। सत्र संचालन विश्वविद्यालय की पूर्व विद्यार्थी और पत्रकार संयुक्ता बनर्जी ने किया।

पुस्तकों और समाचारपत्रों का लोकार्पण

- 'माखन के लाल' : पूर्व विद्यार्थियों के अनुभव पर आधारित पुस्तक। इसके संपादक अतिथि शिक्षक विनयश्री नेमा हैं।
- कार्टून कथा : कॉफी टेबल बुक है, जिसमें 9 कार्टूनिस्ट के कार्टून शामिल किए गए हैं।
- प्रणाम उदन्त मार्तण्ड : कुलगुरु संपादकीय टीम में शामिल विद्यार्थियों का समाचार पत्र।
- अभ्युदय : नए सत्र के शुभारंभ पर केंद्रित समाचार पत्रिका। अंग्रेजी भाषा में इस पत्रिका का संपादन पत्रकारिता विभाग के बीए-इंग्लिश जर्नलिज्म के विद्यार्थियों ने किया है।
- पहल : ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध पर केंद्रित विद्यार्थियों का प्रायोगिक समाचार पत्र। यह समाचारपत्र जनसंचार विभाग के विद्यार्थी प्रकाशित करते हैं।

अब देश का दुश्मन हवा में ही होगा धुआं-धुआं!

● खतरनाक 'तारा' का सफल परीक्षण, बड़ी उपलब्धि ● भारत को मिला पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम

नई दिल्ली (एजेंसी)। डिफेंस सेक्टर में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वदेश में ऐसा ग्लाइडेड हथियार बनाया गया है जो बिना गाइड वाले वॉरहेड्स को सटीक निर्देशित हथियारों में बदलने की क्षमता रखता है। हम बात कर रहे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्मेंटेशन की। ये ऐसा मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जो दुश्मन को चंद सेकंड में धुआं-धुआं कर सकती है। हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र ने डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से तारा को डिजाइन और विकास किया है। डीआरडीओ ने एक्स पोस्ट

में देश की नई हथियार प्रणाली के पहले सफल उड़ान की टेस्टिंग का अपडेट दिया है। इसमें बताया गया कि टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्मेंटेशन हथियार की पहली उड़ान परीक्षण 7 मई, 2026 को ओडिशा के तट से दूर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तारा जो एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। ये भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जो बिना गाइड वाले वॉरहेड्स को सटीक निर्देशित हथियारों में बदल देती है। भारत ने ओडिशा तट के पास स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान का परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, साधारण युद्ध के हथियारों को सटीक निर्देश हथियारों में बदलने के लिए विकसित सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हथियार प्रणाली के पहले उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायु सेना और परियोजना से जुड़े उद्योग साझेदारों को बधाई दी।

टीसीएस केस की प्रमुख आरोपी निदा खान गिरफ्तार

● यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाएं आहत करने के हैं आरोप

नासिक (एजेंसी)। नासिक टीसीएस केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी निदा खान को गुरुवार रात छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लिया। निदा पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप हैं। इससे पहले 2 मई को नासिक कोर्ट ने निदा की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज की थी। प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि आरोप गंभीर हैं और उनसे कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। इस दौरान निदा फरार चल रही थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिसर ने बताया था कि निदा खान इस केस की मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

जाति तब खत्म होगी जब समाज बदलेगा

● आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान ● जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों का सहयोग जरूरी

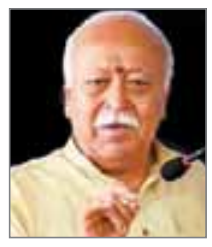

मैसूरु (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण नीति और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून लोगों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जाति आधारित राजनीति तभी खत्म होगी, जब समाज जाति के आधार पर सोचना बंद करेगा। भागवत गुरुवार को कर्नाटक के मैसूरु में महाविद्यापीठ में नेशनल डेवलपमेंट विषय पर लेक्चर के बाद इंटरेक्टिव सेशन में लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने समानता को नारों से नहीं, बल्कि व्यवहार में अपनाने की अपील की।

आरएसएस सरकार नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन

जनसंख्या नियंत्रण और यूसीसी पर सवाल के जवाब में भागवत ने कहा कि संघ सरकार नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को सफल बनाने के लिए लोगों को शिक्षित करना और उनकी भागीदारी जरूरी है। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जनसंख्या नियंत्रण उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जबरन नसबंदी कराई गई, जिससे लोगों में गुस्सा हुआ और बाद में सरकार हार गई।

लोकतंत्र में फैसले धीरे-धीरे होते हैं

उन्होंने कहा, राज्य-दर-राज्य यह आगे बढ़ रहा है। शायद एक दिन पूरे देश में लागू हो जाए। लोकतंत्र में फैसले धीरे-धीरे होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 142 करोड़ लोग मिलकर फैसला करते हैं। जाति व्यवस्था पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि पहले समाज बदलेगा, तभी राजनीति बदलेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि केवल जाति भूलने की बात न करें।

● 5 जिलों के ग्रामीण जवानों के साथ 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे

कश्मीर में एडवांस हथियारों वाली 1500 विलेज गार्ड्स की फौज

जम्मू/श्रीनगर (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने गांव स्तर पर सुरक्षा तंत्र काफी मजबूत किया है। पिछले एक साल में पांच जिलों में 1500 से ज्यादा विलेज डिफेंस गार्ड्स (वीडीजी) को ट्रेनिंग दी गई है।

इसमें हथियार चलाना, टैक्टिकल मूवमेंट, सर्विलांस व इमरजेंसी रिस्पॉन्स शामिल है। वहीं, .303 राइफल की जगह एसएलआर, बुलेटप्रूफ जैकेट व वायरलेस कम्युनिकेशन सेट भी दिए जा रहे हैं। ये ग्रामीण सीमाई इलाकों में जवानों के साथ 12-12

घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। राजौरी के अमित कुमार कहते हैं कि पिछले एक साल में कई बार घुसपैठ की कोशिशें हुईं, पर वीडीजी सदस्यों ने समय रहते सेना और पुलिस को अलर्ट किया। उनके मुताबिक गांव में कोई अजनबी आता है तो लोग तुरंत पहचानकर मूवमेंट की सूचना देते हैं। रात में सुरक्षा बलों के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग भी होती है।

आतंकियों को मारने में कामयाबी

हाल में किश्तवाड़ के सिंहपोरा में स्थानीय लोगों के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को मार गिराया गया। जनवरी में ही कुछ दिन बाद वीडीजी ने एक आतंकी ठिकाना ढूंढने में मदद की। यहां उस्मान के दो और साथी ढेर किए गए। 17 जनवरी, कठुआ का बिलावर इलाका, वीडीजी की मदद से जैश-ए-मोहम्मद का टॉप आतंकी उस्मान मारा गया।

म्यांमार की सीमा से आए उग्रवादियों का हल्लाबोल

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के कमजोंग जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास गुरुवार सुबह हथियारबंद उग्रवादियों ने कई गांवों पर हमला किया। कई घरों में आग लगा दी गई। लोग जान बचाकर जंगलों में भाग गए। पुलिस के मुताबिक, हमला सुबह करीब चार बजे हुआ। उग्रवादियों ने कसोम खुल्लेन थाना क्षेत्र के तांगखुल नागा गांव नामली, वांगली और चोरो को निशाना बनाया। ये गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक किलोमीटर से कम दूरी पर हैं। हमले के दौरान भागने की कोशिश में एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। गांव वालों के मुताबिक, नामली में दो, वांगली में तीन से चार और चोरो में कई घर जलकर राख हो गए।

इन हथियारों को सामान्य मान कर कहीं नजरअंदाज न कर देना !

गिरीश जोशी
संस्कृति अध्येता एवं स्तंभकार

भोपाल में संस्कृति एवं कला की अभिव्यक्ति के लिए एक प्रतिष्ठित मंच है भारत भवन। इसी भारत भवन में पुणे के कोर हेरिटेज संस्था द्वारा अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई हैं। अवसर है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम 'प्रणाम उदन्त मार्तंड' का।

इस प्रदर्शनी को देखते हुए ऐसा लगा मानो हम टाइम मशीन में बैठकर सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में पहुंच गए हो।

यदि देखा जाए तो शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी साम्राज्य का सैन्य उत्कर्ष केवल वीरता पर आधारित नहीं था, बल्कि भूगोल, गतिशील युद्धनीति, हल्के लेकिन प्रभावी अस्त्र-शस्त्र, और स्थानीय संसाधनों के उत्कृष्ट उपयोग पर आधारित था। 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य शिवाजी महाराज ने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी युद्ध प्रणाली विकसित की, जिसने मुगलों, निजाम, पुर्तगालियों, डच, फ्रेंच, सिद्दीयों और बाद में अंग्रेजों तक को चुनौती दी।

इसमें मुख्य भूमिका उनके अस्त्र-शस्त्र की भी थी। उनके शस्त्रों के अनेक प्रकार थे उसमें प्रमुख रूप से थे जैसे तलवारें - ये मराठा सेना में तलवार सबसे प्रतिष्ठित हथियार थी। इसके कई प्रकार प्रचलित थे जैसे सीधी या हल्की वक्र- निकट युद्ध में उपयोगी तेज गति से वार करने के लिए उपयोगी होती थी। दूसरा प्रकार धोप तलवार थी जो लंबी, भारी और दोधारी होती थी ये तलवार कवचधारी शत्रु पर प्रभावी हमला करने के लिए अनुकूल मानी जाती थी। तीसरा प्रकार फिरंगी तलवारों का हुआ करता था। ये तलवारे यूरोपीय ब्लेड + भारतीय मूठ का मिश्रण होती थी। इनको बनाने में पुर्तगाली/यूरोपीय तकनीक का प्रभाव होता था।

एक बड़ी लंबाई की तलवार होती थी जिसे पट्टा या दांड पट्टा भी कहा जाता था ये मराठों का विशिष्ट हथियार थी, यह हाथ में पहनने वाली लंबी तलवार थी। इस तलवार का उपयोग अफ़ज़ल खान के वध प्रसंग में शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवा महाला ने किया था और महाराज की रक्षा की थी।

भाले एवं बरछेः भाला- घुड़सवार सेना का मुख्य हथियार होता था। इससे तेज दौड़ते घोड़े से वार किया जाता था। बरछा- भाले से छोटा होता था, इसका उपयोग पैदल सैनिक किया करते थे। बिचवा/वाघनखः पंजे जैसा गुप्त हथियार जिसे पंजे में पहना जाता था। उसका उपयोग शिवाजी महाराज ने अफजल खान वध में किया था। ढालः चमड़े की ढाल,धातुयुक्त ढाल, हल्की गोल ढाल कवच - सिर, छाती, हाथ आदि की दुश्मन के शास्त्रों के प्रहार से रक्षा के लिए उपयोग होता था।

छत्रपति शिवाजी महाराज के अस्त्र शास्त्रों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण आयाम ये था कि उन्होंने अपने स्वराज्य के भूगोल को भी अपना हथियार बनाया। एक तंत्र खड़ा कर सूचना को शक्ति बनाया। अपने किलों को नेटवर्क बनाया।नौसेना को सुरक्षा कवच बनाया और गति को युद्ध सिद्धांत बनाया। कभी महाराज की युद्ध रणनीतियों पर बात करेंगे। महाराज के जमाने में उपयोग में लाए गए सारे अस्त्रों - शस्त्रों को अपनी आंखों से देखना, अपने हाथों से छूना वाकई रोमांचित करने वाला अनुभव रहा है। आपको भी जब कभी अवसर मिले इस प्रदर्शनी को जरूर देखें और विशेष रूप से अपनी नई पीढ़ी को जरूर दिखाए ताकि वो अपने स्वर्णिम इतिहास से परिचित हो सके।

भोपाल मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट पर वक्फ बोर्ड में सुनवाई

भोपाल। भोपाल में कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो के गुजरने को लेकर शुक्रवार को वक्फ बोर्ड में सुनवाई हुई। स्टे पर बहस के लिए 14 मई की तारीख तय की गई है। इसमें मेट्रो प्रबंधन अपना पक्ष रखेगा। बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर वक्फ संपत्तियों पर विवाद अब कानूनी हो गया है। भोपाल टॉकीज

- **स्टे पर बहस को लेकर 14 मई को अगली तारीख, दोनों रखेंगे अपना पक्ष**

स्थित प्राचीन कब्रिस्तान के नीचे प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन और नारियलखेड़ा की वक्फ जमीन पर निर्माण के खिलाफ कमेटी इंतेजामियां औकाफ-ए-आम्मा ने मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण में दो अलग-अलग प्रकरण दायर किए हैं। कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंसार उल हक और अधिवक्ता इब्राहिम सरवत शरीफ खान पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता खान ने बताया कि दोनों मामलों में मेट्रो निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की

मांग की गई है। शुक्रवार को मामले में सुनवाई की गई। जिसमें अगली सुनवाई की तारीख 14 मई निर्धारित की गई है।

अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन पर यह विवाद- पहले प्रकरण में हमीदिया रोड स्थित मासूमा तकिया अम्मनशाह, मस्जिद नूरानी, मुल्लाशाह और अन्य पंजीकृत वक्फ कब्रिस्तान क्षेत्रों के नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन निकालने की योजना पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई है। याचिका में कहा गया है कि यह कब्रिस्तान न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि शहर के सबसे पुराने और बड़े कब्रिस्तानों में शुमार है, जहां हजारों की संख्या में कब्रें मौजूद हैं। कमेटी का दावा है कि प्रस्तावित मेट्रो लाइन से करीब एक एकड़ क्षेत्र सीधे प्रभावित हो सकता है, जिससे बड़ी संख्या में कब्रों के अस्तित्व और संरचना पर खतरा उत्पन्न होगा। यह भी आरोप लगाया गया है कि मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने अब तक इस क्षेत्र का विस्तृत नक्शा, तकनीकी रिपोर्ट या सुरक्षा आकलन सार्वजनिक नहीं किया है, जिससे आशंकाएं और बढ़ गई हैं। अधिवक्ता खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाईकोर्ट के कई फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि कब्रिस्तान की मूल प्रकृति (नयत) को किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। उन्होंने दलील दी कि भले ही मेट्रो लाइन को अंडरग्राउंड बताया जा रहा हो, लेकिन कब्रिस्तान के नीचे खुदाई, सुरंग निर्माण और कंपन से वहां मौजूद कब्रों और धार्मिक ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा मामला नारियलखेड़ा स्थित वक्फ निशात अफजा (वाके बाग) की जमीन से जुड़ा है, जहां मेट्रो निर्माण कार्य को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।

बरगी क्रूज हादसे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

एमपी में क्रूज-बोट सेवाएं रोकने की मांग, भोपाल निवासी याचिकाकर्ता ने लगाई याचिका

भोपाल। मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में हुए बहुचर्चित क्रूज हादसे का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। भोपाल निवासी कमल कुमार राठी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ में जनहित याचिका दायर कर हादसे को 'गंभीर प्रशासनिक लापरवाही' बताया है। याचिका में दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई, प्रदेशभर के वाटर स्पोर्ट्स और क्रूज संचालन का सेफ्टी ऑडिट कराने तथा जांच पूरी होने तक सभी क्रूज बोट सेवाएं बंद करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 30 अप्रैल

2026 को बरगी बांध में संचालित 'नर्मदा क्रूज' तेज आंधी और ऊंची लहरों के बीच पलट गई थी। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि क्रूज में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। दावा किया गया है कि बोट में 43 से 47 लोग मौजूद थे, जबकि केवल 29 टिकट जारी किए गए थे।

अलर्ट के बावजूद संचालन नहीं रोका

पिटीशन में यह भी कहा गया है कि मौसम विभाग ने 29 अप्रैल को ही तेज हवाओं और खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया था, इसके बावजूद क्रूज़ संचालन नहीं रोका गया। यात्रियों को यात्रा शुरू होने से पहले लाइफ जैकेट उपलब्ध नहीं कराई गईं। एक महिला यात्री के हवाले से याचिका में उल्लेख किया गया है कि नाव में पानी भरने के बाद आनन-फानन में लाइफ जैकेट बांटी गई थीं। जनहित याचिका में राज्य सरकार, एमपी टूरिज्म बोर्ड, आईडब्ल्यूएआई, जबलपुर कलेक्टर और एसपी सहित 8 पक्षकार बनाए गए हैं। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि प्रदेश के सभी जल पर्यटन स्थलों पर संचालित क्रूज़, हाउस बोट और मोटर बोट सेवाओं का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराया जाए, राज्य स्तरीय सुरक्षा नियम लागू किए जाएं और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। पिटीशन में यह भी उल्लेख किया गया है कि बरगी बांध वेटलैंड क्षेत्र में आता है। एनजीटी ने वर्ष 2023 में ऐसे क्षेत्रों में मोटर चालित क्रूज़ संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। इसके बावजूद यहां संचालन जारी रखा गया। मामले में हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई होने की संभावना है।

निर्माणाधीन विकास कार्यों के पूर्ण होने से जिले के विकास की बढ़ेगी रफ्तार : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

जर्जर शासकीय विद्यालयों को चिन्हित कर कराएं मरम्मत, जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

भोपाल। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक है। विकास कार्यों के पूर्ण होने से शहडोल जिले के विकास को नई गति मिलेगी। उक्त निर्देश उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री शुक्ल ने सर्किट हाउस बाणसागर में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने शहडोल-उमरिया मार्ग, ब्यौहारी के विजयसोता पूल निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहडोल-उमरिया मार्ग, ब्यौहारी के विजयसोता पूल, भन्नी सिंचाई परियोजना जैसे अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कलेक्टर समय-सीमा की बैठक में अनिवार्य रूप से करें एवं जल्द से जल्द पूर्ण कर आमजन को उन सुविधाओं का लाभ दिलाए। उन्होंने कहा कि

मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज एवं शहडोल जिले में निर्माणाधीन हेल्थ सेंटरो को यथाशीघ्र पूर्ण कर जनप्रतिनिधियों द्वारा शुभारंभ कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए की शहडोल जिले में संचालित शासकीय विद्यालय जो जर्जर हैं उन्हें सूचीबद्ध कर उनका मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में बनाए जा रहे सांदीपनि विद्यालय के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर जल्द से जल्द से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जनपद पंचायत कार्यालय ब्यौहारी के सामने संचालित शराब की दुकान हटाने के निर्देश कलेक्टर को दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बैठक में मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया, भू अर्जन कार्य में प्रगति, टेटका - शहडोल मार्ग की प्रगति, जयसिंहनगर बाईपास, ब्यौहारी -सपटा मार्ग, जल जीवन मिशन के कार्य, प्रगतिरत कटनी से सिंगरौली डबल रेलवे लाइन के कार्य सहित अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा विकास कार्यों हेतु अपने अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। बैठक में सांसद संसदीय क्षेत्र सीधी डॉ.राजेश मिश्रा, विधायक श्री जयसिंह मरावी, श्री शरद कोल,श्रीमती मनीषा सिंह, कलेक्टर डॉ.केदार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति सहित अन्य जन प्रतिनिधि, अधिकारी एवं जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

वैशाली की किताब 'मेरे घर में पृथ्वी' पर परिचर्चा आज

भोपाल। 'ब्रीद एंड बैलेंस' एवं 'हिन्दुस्तान प्रकाशन' के संयुक्त तत्वावधान में 9 मई को रचनापाठ एवं किताब चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर

कवयित्री वैशाली थापा की पुस्तक 'मेरे घर में पृथ्वी' पर चर्चा के साथ रचनापाठ भी होगा। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में गीत चतुर्वेदी और रक्षा दुबे चौबे अपने विचार साझा करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेमशंकर शुक्ल उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नुसरत मेहदी करेंगी। यह आयोजन 9 मई को शाम 5:30 बजे 'ब्रीद एंड बैलेंस' में आयोजित होगा।

आकाशवाणी के 90वें प्रसारण वर्ष पर वॉकाथॉन

भोपाल। आकाशवाणी के 90वें प्रसारण वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत 8 मई को सुबह 8 बजे आकाशवाणी परिसर में एक वॉकाथॉन (सामूहिक पदयात्रा) का उत्साहपूर्ण एवं सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन केन्द्र प्रमुख लोकेश जाटव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। केंद्र प्रमुख लोकेश जाटव ने कहा कि आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा जनसेवा, जागरूकता एवं विश्वास की सशक्त पहचान रही है।

आकाशवाणी ने सदैव समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य किया है और यह परंपरा आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

वहीं कार्यक्रम प्रमुख शुभम् तिवारी ने कहा कि यह वास्तव में एक स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक अवसर है, जब हम आकाशवाणी के 90 गौरवशाली प्रसारण वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। इस अवसर पर हमें यह संकल्प भी लेना है कि हम अपने समर्पण, रचनात्मकता एवं उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से आकाशवाणी की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और गौरव को निरंतर नई ऊँचाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम, संतुलित आहार एवं सक्रिय दिनचर्या के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। वॉकाथॉन में आकाशवाणी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कैजुअल स्टाफ़ ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

देवास के चिड़ावत गांव की स्थिति ने उजागर की 'हर घर नल से जल' योजना की सच्चाई : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने देवास जिले के चिड़ावत गांव की बदहाल स्थिति को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस गांव को कागजों में 'आदर्श ग्राम' बताया जा रहा है, वहां आज भी ग्रामीणों को खेतों और दूरस्थ स्थानों से डिब्बों में पानी भरकर लाना पड़ रहा है। यह स्थिति केवल एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश में चल रहे जल जीवन मिशन एवं 'हर घर नल से जल' योजना के भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करती है।

श्री पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में 'हर घर नल से जल' का वादा किया था, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के लिए लाखों करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अनेक गांवों में नल तो लगाए गए, पर पानी नहीं पहुंचा। कई स्थानों पर अधूरी पाइपलाइन, बंद पड़ी टंकियां और भ्रष्टाचार के मामलों ने पूरी योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

उन्होंने कहा कि देवास के चिड़ावत गांव का वीडियो अत्यंत पीड़ादायक है। महिलाएं और बच्चे पानी के लिए भटक रहे हैं, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में योजनाएं पूर्ण दर्शाई जा चुकी हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता जनता को सुविधा देना नहीं, बल्कि कागजों पर विकास दिखाकर भ्रष्टाचार को संरक्षण देना है।

श्री पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कई जिलों से लगातार शिकायतें सामने आई हैं। कहीं पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें खराब छोड़ दी गईं, कहीं जल टंकियां निर्माण के कुछ समय बाद ही क्षतिग्रस्त हो गईं और कई गांवों में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा। यह जनता के टैक्स के पैसे की खुली लूट है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के बड़े-बड़े विज्ञापन देती है, लेकिन गांवों की वास्तविकता उन दावों की पोल खोल रही है। यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ होती, तो जल जीवन मिशन में हुए कार्यों का सामाजिक ऑडिट करवाती और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करती। लेकिन आज स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है।

श्री पटवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन के लिए रू. 70,163 करोड़ का प्रावधान किया। मध्यप्रदेश सरकार ने भी इस योजना के लिए हजारों करोड़ रुपये आवंटित किए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब बजट में इतनी बड़ी राशि खर्च दिखाई जा रही है, तब देवास के चिड़ावत जैसे गांवों की माताएं और बहनें बूंद-बूंद पानी के लिए क्यों भटक रही हैं?

उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में योजना ईमानदारी से लागू हुई होती, तो ग्रामीणों को खेतों से डिब्बों में पानी भरकर नहीं लाना पड़ता। सरकार बताये कि हजारों करोड़ रुपये आखिर किसके हित में खर्च हुए?

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने मांग की कि–

देवास जिले के चिड़ावत गांव सहित जल संकट वाले सभी गांवों का तत्काल सर्वे कराया जाए।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुए कार्यों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।

जिन अधिकारियों, ठेकेदारों और एजेंसियों ने कागजों में काम दिखाकर भुगतान लिया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की जाए।

'आदर्श ग्राम' घोषित गांवों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए।

श्री पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और गांव-गांव जाकर भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार एवं झूठे विकास मॉडल की सच्चाई जनता के सामने लाएगी।

संपादकीय

हेट स्पीच पर सुप्रीम फैसला!

देश में हेट स्पीच यानी नफरती भाषा की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 'हेट स्पीच' के लिए क़ानून में फ़िलहाल कई प्रावधान मौजूद हैं और कोर्ट इसमें कोई नया संशोधन लाने के लिए आदेश नहीं दे सकता। कोर्ट ने इस मामले को लेकर 4 को छोड़कर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा अर्थ यह है कि सरकारों के पास वो सभी कानून मौजूद हैं, जिनसे हेट स्पीच को सख्ती से रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा करने की उनकी नीयत और इच्छाशक्ति चाहिए। गौरतलब है कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने कई याचिकाएँ थीं। कुछ याचिकाओं में माँग की गई थी कि हेट स्पीच के मुद्दे पर क़ानून में संशोधन होना चाहिए। ऐसे नए प्रावधान लाने चाहिए जिससे हेट स्पीच को रोका जा सके। जबकि कुछ की माँग थी कि कोर्ट को विशेष जाँच टीम बना कर हेट स्पीच की घटनाओं पर जाँच की निगरानी रखनी चाहिए। कई याचिकाएँ कुछ कथित हेट स्पीच की घटनाओं के खिलाफ़ थीं। इसमें याचिका दायर करने वालों की माँग थी कि ऐसे नफ़रती भाषण देने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इनमें भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के भाषणों, हरिद्वार और दिल्ली में धर्म संसद से जुड़े केस, कोरोना काल में तबलीग़ी जमात के बारे में दिए गए बयान जैसे मामले शामिल हैं। एक मामला सुदर्शन टीवी चैनल से जुड़ा था। अगस्त 2020 में सुदर्शन टीवी के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाण ने कथित 'यूपीएससी जिहाद' के बारे में ट्विटर (अब एक्स) पर टिप्पणी की थी। इन्हीं तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने विगत 29 अप्रैल को फैसला देते हुए 4 को छोड़ बाकी याचिकाएं खारिज कर दीं। चार याचिकाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इनमें प्रशासन ने कोर्ट के सामने अपना जवाब दायर नहीं किया था कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। इसलिए वे इन केस में आगे सुनवाई जारी रखेंगे। बाक़ी मामलों में कोर्ट ने राज्यों से 'स्टेटस रिपोर्ट' माँगी थी। कोर्ट ने कहा कि उन मामलों में एफ़आईआर दायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के क़ानून और कोर्ट के पहले के फ़ैसलों से यह साफ़ है कि अगर किसी संज्ञेय जुर्म (कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस) की जानकारी पुलिस को दी जाती है तो पुलिस को एफ़आईआर दायर करना ज़रूरी है। संज्ञेय जुर्म यानी ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ़्तार कर सकती है। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो तो किसी व्यक्ति के पास अनेक क़ानूनी विकल्प हैं. वे वरिष्ठ पुलिस अफ़सर के पास शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट भी मामले में कार्रवाई करने से मना कर दे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। पुलिस में एफ़आईआर दायर करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास शक्ति होती है कि वे अलग-अलग पड़ाव में जाँच पर निगरानी रख सकें। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच के मुद्दे पर भारत में अनेक क़ानून हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कानून विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। कुछ का मामला है कि कोर्ट ने कानून के दायरे में ही अपना फैसला दिया है जबकि कुछ का मानना है कि कोर्ट ने हेट स्पीच पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए सरकार को कानून में संशोधन का कोई आदेश नहीं दिया है, जबकि कोर्ट चाहती तो ऐसा कर सकती थी।

तमिलनाडु : थलपति विजय की 'क्वांटम लीप'

नजरिया

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

क्वांटम लीप' वैज्ञानिक शब्दावली का टर्म है, लेकिन यदि भारतवर्ष की बीती अर्द्धशती की राजनीति का सिंहावलोकन करें तो इस टर्म को दक्षिण भारत की राजनीति के सन्दर्भ में बाखूबी प्रयुक्त किया जा सकता है। दक्षिण भारत के मतदाताओं में सिने-कलाकारों के प्रति गजब का क्रेज है और वहां लंबी नीहारिका है, जिसने राजनीति में चमकीली सफलता अर्जित की। एनटी रामाराव, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, करूणानिधि और पवन कल्याण की फेहरिस्त में अब एक नया नाम आ जुड़ा है। यह नाम है विजय थलपति का, जो सिने-स्टारडम से लंबी छलांग लगाकर तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण प्रांत के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे हैं।

थलपति यानि कमांडर के नाम से विख्यात विजय का पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। अगले माह 22 जून को वह अपने जीवन के बावन वर्ष पूरे कर लेंगे। उनके पिता एसए चंद्रशेखर ईसाई हैं और मां शोभा हिन्दु। यह इसी पृष्ठभूमि का प्रभाव है कि वह मंदिर भी जाते हैं और चर्च भी, साथ ही उन्हें मस्जिद और दरगाह जाने में कोई संकोच नहीं होता। तमिल-सिनेमा से उनका नाता इस नाते पुराना है कि उनके पिता सिने निर्देशक रहे हैं और कांग्रेस के प्रति उनकी रूझान रही है। चेन्नै में जनमे विजय की पढ़ाई भी स्थानीय लोयोला कॉलेज में हुई और उन्होंने शुरूआती डेढ़ दो दशक तक अपना ध्यान पूरी तौर पर फिल्मों पर केंद्रित किया। इसके बाद वह सार्वजनिक जीवन की ओर मुड़े और फैन क्लबों के जरिये उन्होंने सधे हुये कदमों से वह यात्रा शुरू की, जिसकी परिणति चार मई, 26 को उनकी आशातीत राजनीतिक सफलता और उपलब्धि में हुई। थलपति विजय आज तमिल सिनेमा की सफलतम और शीर्षस्थ कमाऊ सितारों की सूची में शुमार हैं। वह अब तक 69 फिल्मों में लीड-भूमिकाओं में आ चुके हैं और फिल्म में उनकी मौजूदगी टिकट खिड़की पर सफलता की गारंटी मानी जाती है। यदि उनके जीवन-वृत्त को खंगालें तो दिलचस्प तौर पर पिता के प्रोत्साहन और प्रेरणा पर उन्होंने अपना सिनेमाई सफर सन 1984 में तमिल फिल्म 'वेट्री' में बाल कलाकार के तौर पर किया। पिता द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों में बाल भूमिकाएं निभाने के उपरांत 18 वर्ष की वय में 1992 में उन्हें 'नालैया थीर्पु' में नायक की भूमिका निभाने का मौका मिला। तदंतर पूर्व उनक्कगा, लव टुडे, कडलुक्कू मरियाधई, थुल्लथ, मानामम थुल्लम, कुशी, प्रियम्मनावले और फ्रेंड्स आदि ने एक दशक में उन्हें तमिल सिने उद्योग में शिखर पर पहुंचा दिया। इसके बाद के ढाई दशक रूपहले पर्दे पर उनकी धूम की दहाई थी। वह तमिल सिने दर्शकों की पहली पसंद बनकर उभरे। अंततः सन् 2024 में उन्होंने सिनेमा को 'सायोनारा' कह दिया और राजनीति उनका पहला प्रेम बनकर उभरी। दिलचस्प बात है कि इसी साल आई उनकी फिल्म का टाईटिल था 'ग्रेटेस्ट आफ आल टाइम। मगर उनकी अंतिम फिल्म जन नायगान का रिलीज होना अभी शेष है।

फरवरी, सन् 2024 में विजय ने अपनी नयी पार्टी लॉंच की। द्रविड़ पार्टियों के वर्चस्व की अर्द्धशती के परिप्रेक्ष्य में यह एक साहसिक कदम था, लेकिन यह साहस उन्हें फला। नयी पार्टी का उन्होंने नाम रखा तमिलगा वेट्री कझगम। बताते हैं कि वह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के इच्छुक थे। इसके वास्ते उन्होंने राहुल गांधी से भेंट व चर्चा भी की थी, लेकिन द्रमुक से जारी गठबंधन और स्थानीय ईकाई के परामर्श से वह ऐसा करने से हिचक गये। फलतः कांग्रेस और टीवीके मेल सिरे नहीं चढ़ा।

यह सोचना भ्रामक होगा कि थलपति की सियासी सफलता दो वर्ष की सक्रियता का नतीजा है। इसके पीछे बिलाशक उनके फैन क्लबों की गतिविधियों का हाथ है। थलपति ने सन् 2009 में अपने फैन क्लब विजय मक्काल इयक्कम की नींव डाली थी। समय के साथ ये फैन क्लब समूचे तमिलनाडु में ओरछोर फैल गये। इन क्लबों ने राहत कार्यों, शिक्षण, प्रशिक्षण और चैरिटी का काम हाथ में लिया। इसने उनकी सिनेमाई छवि में हातिमताई के रंगे भरे। आपदा पीड़ितों के लिये दरवाजे और थैलियां खोलने ने जननायक की संवदेनशील छवि अर्जित करने में मदद की। इसके बावजूद जब-तब उनकी सियासत में रूचि और रूझान सामने आती रही। सन् 2011 के चुनाव में उन्होंने अन्नाद्रमुक-नीत गठबंधन को समर्थन दिया। सन् 2019 में उन्होंने नागरिकता अधिनियम का यह कहकर विरोध किया कि इससे सामाजिक-धार्मिक सौमनस्यता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सन् 2022 में उनके फैन क्लब के सदस्यों ने निकाय चुनावों में शिरकत की और 115 सीटों पर सफलता पाई। उनकी बढ़ती लोकप्रियता प्रमाण 27 सितंबर, 2025 को करूर में तब मिला, जब उनकी रैली में भगदड़ से 41 लोगों की जानें गयीं। इस पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की और हताहतों के लिये धनराशि वितरित की। थलपति विजय की खूबी है कि उन्होंने करीब 85000 फैन क्लबों की मजबूत चुनावी मशीनरी में बदल दिया है। ये क्लब उन्हें कार्यकर्ता, चुनावी भीड़ और समर्थक तो जुटाते ही हैं, उनकी 'नायक' की छवि में निर्मित करते हैं। जब वह भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात करते हैं तो यह छवि उसमें सहायक होती है। उनकी यह इमेज़ दक्षिण भारतीय मतदाताओं की सितारों के प्रति नैसर्गिक चाहत को पोसती है। मान सकते हैं कि सन् 2011 में जयललिता को समर्थन की परिणति ने उनके मन में सियासत में शिरकत का बिरवा रोपा था। बहरहाल, ताजा चुनाव में टीवीके की 108 सीटों पर कामयाबी से वह नया इतिहास रचने में सफल रहे हैं। उन्होंने स्वयं दो सीटों पेरांबूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ा और विजयी रहे। यह भी तय है कि बहुमत से कुछ सीटों का फासला पूरने में वह सफल होंगे। तयशुदा है कि दोनों लेफ्ट पार्टियां भी उन्हें समर्थन देंगी। नतीजों के बाद वह राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा जता चुके हैं। कांग्रेस ने समर्थन के साथ यह शर्त जरूर नत्थी की है कि विजय सांप्रदायिक ताकतों से दूरी बरतेंगे, संवैधानिक मूल्यों का पान करेंगे, थंथाई पेरियार के सामाजिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता रखेगें और पेरूंथ लैवर कामराज के गौरवशाली दिनों की वापसी के लिये जतन करेंगे। जहां तक विजय के विचारों की बात है वह स्पष्ट कर चुके हैं कि द्रमुक उनकी राजनीतिक बैरी है और बीजेपी वैचारिक शत्रु। चुनाव प्रचार के दरम्यान उन्होंने इतनी अधिक लोकलुभावन घोषणायें की हैं कि वित्तीय कारणों से उन्हें अमल में लाना कठिन होगा। तमिल मतदाताओं को उनसे उम्मीद इस नाते है कि वह फैन क्लबों के जरिये मुफ्त कैंटीन, कंप्यूटर वितरण, ब्लड डोनेशन और राहत कार्यों का अभियान चलाते रहे हैं। मीडिया की चकाचौंध से बचने के लिये बाज वक्त वह रूमाल से चेहरा ढंककर अथवा दुपहिया वाहन पर बैठकर घटना स्थल पर गये। वह राहुल गांधी ही नहीं अन्ना हजारे और नरेन्द्र मोदी से भी मिल चुके हैं। वह करूणानिधि और एमजीआर के प्रशंसक हैं। सामाजिक न्याय उनके लिए मायने रखता है। कम ही लोगों को ज्ञात होगा कि वह कुशल और पुरस्कृत गायक हैं और इलैयाराजा और एआर रहमान तक के लिए गा चुके हैं।

हां, उनका निजी जीवन विवाद और नुक्ताची का शिकर रहा है। उन्होंने सन् 1999 में संगीता सोर्नालिंगम से शादी की थी, जो श्रीलंका में जनमी ब्रिटिश तमिल युवती थीं। संगीता ने गत वर्ष उनसे तलाक की अर्जी लगाई है, अलबत्ता उनकी दोनों संतानों से उनके रिश्तों को इससे बूझा जा सकता है कि उनका पुत्र जेसन संजय और पुत्री दिव्या साशा उनके साथ क्रमशः वेट्टेकरन और थेरी में रुपहले पर्दे पर आ चुके हैं। 6.25 बिलियन संपत्ति के स्वामी थलपति विजय का तृषा कृष्णन के साथ प्रेम प्रसंग संप्रति लोगों की जुबान पर है, लेकिन आज की राजनीति में नायकों के प्रेम-प्रसंग और विवाहेतर संबंध समर्थकों और प्रशंसकों के लिये मायने नहीं रखते, अतः थलपति का पर्फामेन्स ही तय करेगा कि वह राजनीति में कितनी लंबी और कैसी पारी खेलते हैं?

स्त्री सशक्तिकरण की बदलती भूमिका

राजनीति

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

स्त्री सशक्तिकरण के कथित स्थापित मानदंड पश्चिम बंगाल के 2026 के चुनाव परिणामों में टूटते दिखाई दिए हैं। इन परिणामों से जुड़ी तीन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि स्त्री अस्मिता से जुड़े सुरक्षा के प्रश्नों का समाधान उच्च शिक्षा, उच्च पद या कार्पोरेट चकाचौंध करने वाली दीवारों के भीतर से नहीं, बल्कि स्वयं स्त्री के साहस, संघर्ष और आत्मचेतना के प्रखर आत्मबल से निकलेंगे। बीते कुछ समय में देखने में आया है कि एक वे महिलाएं हैं, जो उच्च शिक्षित और मजबूत आर्थिक स्वावलंबी होने के बावजूद कार्पोरेट बनाम धार्मिक जिहाद की शिकार बन गईं। हमें अशोक खरात के कथित अतींद्रिय-अलौकिक मायालोक से आसक्त होकर अपनी दैहित शुचिता गंवा बैठीं। जबकि विवाहित स्त्री के सम्मान और भरोसे का ही नहीं, सनातन मूल्य और संस्कार का भी यही सर्वाधिक प्रतिष्ठित गुण है। इन महिलाओं में महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष भी शामिल रही हैं। उच्च पद पर आसीन इस महिला का दायित्व था कि वह अंधविश्वास के पाखंड से महिलाओं को जागरूक व सचेत करती, जबकि वह खुद चमत्कार के आकर्षण में अपने चरित्र की पवित्रता खो बैठी। ऐसी ही जटिल स्थितियों के बीच बंगाल के विधानसभा चुनाव से तीन ऐसी महिलाओं की जीवटता देखने को मिली है, जो बड़े सामाजिक बदलाव का संदेश देती हैं।

बुलंद स्त्रियों की पहली आवाज है, संदेशखाली की रेखा पात्रा! यह वह साहसी महिला है, जिसने संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस नेताओं के यौन दुष्कर्म को झेला था। इन नेताओं के उत्पीड़न की हवस की रेखा अकेली शिकार नहीं थी, ज्यादातर युवा स्त्रियों को इन हवस के भूखे भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया हुआ था। रेखा अपने मुख को घूंघट में छिपाकर बैठी नहीं रह गई, अपितु उसने घूंघट हटाकर संदेशखाली के बलात्कारियों के विरुद्ध मुख्य आवाज बन गई। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और उसके सहयोगी शिवप्रसाद हजारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। हजारी को इसी शिकायत पर गिरफ्तार भी किया गया था। यही वह शक्तिस्वरूपा रही, जो तृणमूल के नेताओं के विरुद्ध पीड़ित महिलाओं के समूह का नेतृत्व करते सड़क पर उतरी और आंदोलन का चेहरा बन गई। जब स्त्री के विद्रोह के स्वर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचे तो उन्होंने रेखा से फोन पर बात कर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बसीरहाट से उम्मीदवार बना दिया। वे हारीं जरूर, लेकिन उन्होंने आंदोलन के वातावरण को निरंतर गरम बनाए रखा। इस संघर्ष का परिणाम रहा कि उन्हें हिंगलगंज आरक्षित विधानसभा सीट से भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया। अब वे विधायक हैं।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रत्ना देबनाथ ने बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने का संकल्प तब लिया, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कामकाजी स्त्री की मजबूरी को समझे बिना कह दिया था कि स्त्रियों को रात आठ बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ममता के इस बयान के बाद रत्ना बेटी के प्रतिकार की भावनात्मक प्रतीक बन कर न्याय के लिए जुट गईं। उन्हें जब समाज का सहयोग मिलने लग गया, तो उनमें राजनीतिक चेतना विकसित होने लग गई। तृणमूल नेता व कार्यकर्ताओं की धमकियों के भय से वे निर्भय हो गईं। 2025 में वे मजबूती से लड़ने के लिए भाजपा में सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गईं। तृणमूल द्वारा अपराधियों को खुला संरक्षण देने के चलते यह पहल जरूरी थी। यहीं उन्होंने शपथ ली, कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, वे बालों में कंधी नहीं करेंगी। यह संकल्प द्रोपदी के द्वारा चीरहरण के बाद ली उस कसम की प्रतीक थी, जिसमें उन्होंने विद्वानों की भरी सभा में कहा था कि 'अब मैं अपनी चोटी तब तक नहीं बांधूगी जब तक दुशासन के लहू को बालों में नहीं डाल लूंगी।' रत्ना देबनाथ के इस संकल्प की ध्वनि मोदी के कानों में गूंजी और उन्हें पानीहाटी विधानसभा से उम्मीदवार बना दिया। इस पीड़िता के करुणा से आप्लवित स्वरों ने मतदाताओं को भीतर तक झकझोर दिया। फलतः उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को अट्ठाइस हजार से भी ज्यादा मतों से पराजित कर दिया।

एक और घरेलू कामकाजी महिला हैं, कलिता मांझी! चार घरों में काम करके परिवार चलाती हैं। भाजपा की मुखर समर्थक होने के कारण उन्हें तृणमूल कार्यकर्ताओं के नियमित उत्पीड़न का दंश झेलना पड़ा है। बावजूद वे दृढ़ता के साथ भाजपा के साथ दमदारी से जुड़ी रहीं। इसका प्रतिफल उन्हें और ग्राम आरक्षित सीट से भाजपा की उम्मीदवारी हासिल हो गई। उन्होंने तृणमूल के उम्मीदवार को 12 हजार से भी ज्यादा मतों से हरा दिया। इस महिला की जिजीविषा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने गरीबी और उत्पीड़न की पीड़ा एक साथ झेलते हुए अपना राजनीतिक संघर्ष अनवरत रखा। इन तीनों महिलाओं की विपरीत परिस्थितियों में जीवटता देखते हुए कहना पड़ेगा कि उनकी ये उपलब्धियां केवल दलगत राजनीतिक शक्ति और संसाधन मिल जाने की सफलता नहीं है, बल्कि संकल्प सिद्धी की संजीवनी को स्वस्फूर्त अंतर-प्रेरणा से ऊर्जावान बनाए रखने के चलते मिली है। ये तीनों महिलाएं अलग-अलग पृष्ठभूमि से आती हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव की भावना इनकी एक जैसी है। इनकी जीत ने तय कर दिया है कि अब मतदाता परंपरागत दलगत राजनीति की मानसिकता से मुक्त होकर उन चेहरों में उम्मीद तलाशने लगे हैं, जो संघर्श की जमीन से उपजीं और विपरीत परिस्थिति में खड़ी रहीं। अपनी राजनीतिक जमीन की बुनियाद पुख्ता करती रहीं। इनकी राजनीतिक उपलब्धियां, वंदनीय, अविस्मणीय एवं तक अनुकरणीय हैं।

दूसरी तरफ देश में ऐसी उच्च शिक्षित महिलाओं की श्रृंखला देखने में आ रही है, जो हर प्रकार से अर्थ व अधिकार संपन्न हैं। परंतु कार्पोरेट जिहाद का शिकार होकर मतांतरित होने को मजबूर हो गईं थीं। इस कड़ी में नासिक की टीसीएस कंपनी में कार्यरत इंजीनियर व एमबीए महिलाएं पदोन्नति, उत्तम अवसर के लालच में आकर इस्लामिक वेषभूषा, इबादत और रहन-सहन में ढलने लग गईं। सनातन संस्कारजन्य रीति-रिवाजों को बदलने लगीं। यहां तक की रोजे रखने लगीं, नमाज पढ़ने लगीं। इन तथ्यों की प्रामाणिकता एनआईए की जांच सीसीटीवी के फुटेज से तय हुई है। उच्च तकनीक में दक्ष ये महिलाएं मानसिक रूप से इतनी कमजोर और विचार के स्तर पर सतही साबित हुईं। ये कंपनी के मुस्लिम प्रबंधकों द्वारा इस्लाम धर्म के महिमामंडन के चलते उसकी गिरफ्त में आती चली गई और धर्मांतरण करने को आतुर होती चली गईं। यह कारपोरेट जिहाद हिंदुओं की अस्मिता के समक्ष ऐसी चुनौती बनकर उभरा है, जिससे सामान्य परिस्थितियों में निपटना आसान नहीं है?

एक वे महिलाएं हैं, जो कथित ढोंगी अशोक खरात के फरेब में आकर स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हो जाती हैं। ये सब महिलाएं विवाहित प्रौढ़ाएं हैं। आईएएस, आईपीएस और राजनेताओं की पत्नियां हैं। ये इस स्वयंभू धर्मगुरु के चंगुल में फंसती चली गईं। यहां तक की महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर इसके चंगुल में आ गई। उत्तम शिक्षा और उच्च पद की प्राप्ति के बाद ऐसी महिलाओं से उम्मीद तो यही की जाती है कि ये किसी भी शोषण और अन्याय के विरुद्ध अपनी वाणी को बुलंद करेंगी। उजले चेहरों को बेनकाब करेंगी? उनका घिनौना चरित्र उजागर करेंगी ? लेकिन देखने में आया कि धर्मांतरण और अंधविश्वास के लिए यौन शोषण के लिए भी समर्पित दिखाई दीं।

अभी तक हम यह सुनते चले आ रहे थे कि फिल्मों में काम पाने के लिए अभिनेत्रियां अपना शरीर निर्माता-निर्देशकों को सहज रूप में सौंप देती हैं। राजनीति में भी यह स्थिति बनती रही है। कुछ फिल्मी पर्दे की नायिकाओं ने इस दुराचार का 'मी-ट' अर्थात् 'मैं भी बोलूंगी' के बहाने 2018 में कुछ नायिकाएं मुखर भी हुईं। लेकिन उन्होंने यह सब संबंध बनाने के पूर्व नहीं, बल्कि लाभ उठाने के बाद किया। इन बयानों को कथित प्रगतिशीलों ने परिवर्तन की भूख माना तो कुछ ने इस मी-टू को उपभोक्तावादी संस्कृति का मसालेदार हिस्सा माना। अब कार्पोरेट जिहाद और पाखंडी ढोंगी के समक्ष अर्थ-संपन्न, अनुभवजन्य प्रौढ़ाओं के समर्पण को हम क्या मानें ? क्या कहें? नौकरी बचाए रखने की लालसा या कथित 'योनि-पूजा' के बहाने उत्कट भोग की तीव्र उत्कंठा ? दूसरी तरफ हमारे सामने रेखा पात्रा जैसी वह स्त्री है, जो अपने साथ हुए दुश्कर्म के विरुद्ध आवाज उठाती है, बल्कि दोषियों को कानून के कठघरे में ला खड़ा करती है। वह बहुत ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं, है, लेकिन देह की पवित्रता और संस्कारों की मर्यादाओं को बखूबी जानती है। वह उस प्रचलित मिथक से मुक्त होती है कि बलात्कारी ने उसका 'सब-कुछ' लूट लिया ? वह समाज की इस मान्यता को भी परे धकेलती है कि लूटी गई आबरू कभी बहाल नहीं होती ? क्योंकि स्त्री का जननांग ऐसा अंग है, जो अवैध शारीरिक संबंध हों या जबरन बलात्कार, उसकी दैहिक शुचिता हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। हालांकि अब यह अच्छी बात है कि यौन-शुचिता के मूलयबोध का भ्रम खंडित हो रहा है। अब समाज न केवल लव जिहाद के संकट से गुजरी महिलाओं को स्वीकार रहा है, बल्कि कार्पोरेट जिहाद, मतांतरण और अंधविश्वास के पाखंड की शिकार हो चुकी महिलाओं के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उत्पीड़ित स्त्रियों को सम्मान उचित है, लेकिन इन स्थितियों से स्त्रियों और उनके परिजनों को सचेत रहने की जरूरत है।

जिम्मेदार उपयोग क्यों जरूरी?

सोशल मीडिया

संध्या अग्रवाल

लेखक साहित्यकार हैं।

आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोग एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और देश-दुनिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन जहां सोशल मीडिया ने संवाद को आसान बनाया है, वहीं इसके दुरुपयोग ने कई गंभीर समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सूचना को तेजी से फैलाने का माध्यम है। किसी भी घटना की जानकारी कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। यह प्लेटफॉर्म लोगों को अपनी बात रखने का अवसर देता है और समाज में जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई सामाजिक अभियानों और जन आंदोलनों को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक समर्थन मिला है।

हालांकि, इसके नकारात्मक पहलू भी उतने ही गंभीर हैं। बिना सत्यापन के जानकारी साझा करना आज एक आम प्रवृत्ति बन गई है। इससे फेक न्यूज़ और अफवाहों का प्रसार होता है, जो समाज में भ्रम और तनाव की स्थिति पैदा करता है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर बढ़ती लत विशेष रूप से युवाओं के लिए चिंता का विषय है। अत्यधिक उपयोग से पढ़ाई, कार्य और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से भी कई खतरे जुड़े होते हैं। साइबर अपराध, धोखाधड़ी और डेटा चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार लोग अनजाने में अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा कर देते हैं, जिसका गलत उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन ट्रोलिंग और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी सामाजिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। इन सभी समस्याओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए। इसका उत्तर है–जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ। प्रत्येक उपयोगकर्ता को यह समझना होगा कि वह जो भी सामग्री साझा कर रहा है, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक है। साथ ही, समय का संतुलित उपयोग और डिजिटल अनुशासन भी बहुत जरूरी है। सरकार और संबंधित संस्थानों को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना, फेक न्यूज़ पर नियंत्रण और लोगों को जागरूक करना समय की मांग है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि नई पीढ़ी सोशल मीडिया का सही और सुरक्षित उपयोग कर सके। अंततः, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन है, जिसका उपयोग समाज के हित में भी किया जा सकता है और नुकसान के लिए भी। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। यदि हम जिम्मेदारी और समझदारी के साथ इसका उपयोग करें, तो यह समाज को जोड़ने और आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कारवाँ गुजर गया झालमुड़ी देखते रहे

व्यंग्य

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

घोष बाबू रोज की तरह टीवी ताने बैठे हैं। टीवी तो मंथली रिचार्ज से चलता है। घोष बाबू किस रिचार्ज से चल रहे हैं पता नहीं। बंगाल से बाहर बैठा बंगाली बंगाल में ही होता है। बोलते हैं टीवी मुझे नहीं छोड़ता है। लेकिन मिसेस घोष का कहना है ये टीवी को नहीं छोड़ रहे हैं। माछेर झोल और राशोगुल्ला भी अब असरदार नहीं है।

'और क्या चल रहा है घोष बाबू?' सुखवीन्दर ने आते ही पूछा।

'आपको मालूम नहीं!! सब तरफ झलमुड़ी चल रहा है।' सुखवीन्दर पर एक नजर डालते हुए जवाब दिया।

'ओ बादशाओ मैं आपका हाल-चाल पूछ रहा हूं।'

'हाल-चाल भी झालमुड़ी हैं। मतलब झालम झाल है, टीवी पर खबरें कम झाल ज्यादा चल रही है।'

'फुर्सत में हो क्या? चलो।' सुखवीन्दर से सोचा थोड़ा टहला जाए साथ साथ।

'फुर्सत कहाँ है, टीवी देख रहा हूं।'

'टीवी देखना भी कोई काम है!... क्या देख रहे हो?

'झालमुड़ी।... हर चैनल पर झालमुड़ी ही है।'

'अरे क्या झालमुड़ी झालमुड़ी!! चुनाव हो गए, सरकारें करीब करीब बन गई। अब क्या बचा है देखने को!'

'झालमुड़ी बची है ना।... चुनाव से ज्यादा धमा धम अब हो रही है। बंगाल का झालमुड़ी में बड़ा जोर हैं।'

'छोड़ो प्राजी, चल्लो आपको लस्सी वस्सी पिलवाते हैं। दिमाग़ ठंडा हो जाएगा जी। अब खबरों से क्या हासिल होना है।' सुखवीन्दर ने दबाव डाला।

'पहले एक बात बताओ, चुनाव का हासिल क्या है?'

'चुनाव का हासिल तो सरकार है घोष बाबू।'

'अरे सरकार तो पहले भी थी। थी या नहीं?... देश को नया क्या हासिल हुआ?...

'आप ही बताओ।'

'झालमुड़ी।'

'पहले तो आप बाद महंगाई के आलावा कोई बात नहीं करते थे घोष बाबू !!'

'अरे समझते नहीं हो!! महंगाई इसमें कवर हो गया ना। झालमुड़ी का रेट दस रुपया फिक्स है प्याज़ के साथ। दस में गरीब भी खा सकता है। अब महंगाई कहाँ है! एक ही झटके में महंगाई खतम।...'

'फिर भी दो रोटी की समस्या तो है ही। कोई रोज-रोज झालमुड़ी थोड़ी खा सकता है। रोटी तो चाहिए ही।'

'अब झालमुड़ी आ गई, रोटी का क्या काम। ब्रेक फ़ास्ट झालमुड़ी, लंच झालमुड़ी, डिनर झालमुड़ी। शादी सगाई झालमुड़ी, तीसरा तेरही झालमुड़ी। चाट बाजार झालमुड़ी, होटल फाइव स्टार झालमुड़ी।... उसके बाद भी किसी को रोटी चाहिए तो... मेक एफर्ट एंड इन्जवाय... कोई रोकेगा नहीं। फ्रीडम है... पक्का वाला लोकतंत्र... यू नो।'

'और रोजगार का क्या? जवान बच्चे पढ़ लिख कर खाली हाथ बैठे हैं!!'

'क्यों बैठे हैं! चाय पकौड़ी बनाते बेचते। अब झालमुड़ी बेच सकते हैं। ऑप्शन है, फिर कहोगे विकास नहीं हुआ! लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहे तो उसके लिए कांग्रेस के आलावा कोई भी सरकार जिम्मेदार नहीं है।'

'कैसी बातें कर रहे हो दादा आप! अस्पताल, स्कूल कालेज... इनको भूल गए!'

'झालमुड़ी खाने से कोई बीमार नहीं होता है। सरसों का तेल सेहत के लिए अच्छा है। हमारा माछेर झोल सरसों के तेल में ही बनता है। झालमुड़ी खाओ स्वस्थ रहो, मस्त रहो।... तुमको एलर्जी है क्या झालमुड़ी से?'

'ना जी ना, हमारी देशभक्ति पर शक न लाओ। मैं तो पहले दिन से ही खा रहा हूं झालमुड़ी, प्याज़ डाल के।... आप ऐसी बात ना किया करो दादा, दीवारों के भी कान हुआ करते हैं।' सुखविंदर ने उठते हुए धीमी आवाज में कहा।

संवेदना से सुधरेंगे, केदारनाथ यात्रा के संकट

वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

केदारनाथ समुद्र तल से करीब 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदाकिनी नदी इसकी सीमा पर है। वर्ष 2026 के 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के ग्यारह दिन पहले मंदिर के पीछे के ग्लेशियल क्षेत्र से भारी भूस्खलन हुआ है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक के पैदल मार्ग में आती बाधाओं को दूर किया जा रहा है। वर्ष 2024 के 30 जून को केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आये श्रद्धालुओं ने पांच बजे सुबह बर्फ की बौछार मंदिर के पीछे गांधी सरोवर के क्षेत्र में देखी। कुछ का कहना था कि उन्हें लगा बर्फ के पहाड़ ही टूट गये हों। वर्ष 2022-23 में भी कहते हैं ऐसा हुआ था। जून-जुलाई 2024 का संदर्भ हो या आज का अथवा केदारनाथ महा त्रासदी 2013 का, केदारनाथ पैदल मार्ग के पास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय जोखिमों में बढ़ौत्री ही हो रही है।

31 जुलाई 2024 को लिंचैली जंगल चट्टी के ऊपर बादल विस्फोट से लिंचैली व भीमबली में बेहद खौफनाक मंजर दिखा था। केदारनाथ से गौरीकुंड के बीच हजारों यात्री फंसे हुये थे। लिंचैली में फंसे यात्री ज्यादा मुसीबत में थे क्योंकि न सिर्फ मंदाकिनी नदी, बल्कि बगल के पहाड़ से आता नाला भी पानी के साथ मलवा ला रहा था। ऐसी घटनाओं को आम कहने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। पूरा तंत्र ऐसे बयान देने लगता है। यदि ये सामान्य हो गई हैं, तो जलवायु बदलाव के दौर में केदारनाथ धाम की सुरक्षा के लिये विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, लेकिन अब इतनी सुविधायें जुटा ली गई हैं कि प्रतिदिन वहां बीस-पच्चीस हजार यात्री समा सकते हैं। इतने ही रास्तों पर भी रहते हैं। इससे सीमित क्षेत्र में हजारों इंसानों की उपस्थिति व गतिविधि से 'हीट आइलैंड्स' बनने की संभावनायें बढ़ी हैं। खुद यात्री कहते हैं अब तेज धूप झेलना मुश्किल होता है।

पता नहीं केदारनाथ के तापक्रम परिवर्तन पर अलग से अध्ययन हुये हैं कि नहीं, किन्तु पूरे हिंदुकुश हिमालय पर ही जलवायु बदलाव के खतर बढ़े हैं। पश्चिमोत्तर हिमालय में 1991 के बाद औसत तापमान 0.66 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की दर दुगुनी हो गई है और पहाड़ बर्फ-विहीन हो रहे हैं, परन्तु केदारनाथ जैसी जगहों के आसपास यदि ये होता है तो हम वैश्विक वजहों से इसे होना नहीं कह सकते। वैश्विक कारणों के साथ उन पर स्थानीय आघाती कारण भी जुड़ रहे हैं। फरवरी 2021 में नीति घाटी में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा में भारी बाढ़ आई थी।

केदारपुरी जिस भूखण्ड में बसी है उसके नीचे हिमोड और भूस्खलनों का मलवा है। इस क्रम में यहां के 'ड्रैनेज पैटर्न' पर भूमिगत जल-प्रवाह, भण्डारित जलराशि की स्थिति व 'सरफेस रनऑफ' के पैटर्न व आंकड़ों का अध्ययन करिये। इन विश्लेषणों से समझा जा सकता है कि भू-धंसाव के जोखिम के बीज तो यहां ही जम रहे हैं। तेज बारिश में तात्कालिक रिसाव से भले ही बच जायें, परन्तु जमीन में जल का रिसाव भूमिगत मिटटी, चटटानों की दरारों, अपभ्रंशों आदि की मार्फत कमजोर करता है। ऐसे में भूस्खलन व भू-धंसाव की समस्या बढ़ जाती है।

हेलीकॉप्टरों की आवाजाही भी यहां काफी हो रही है, निर्माण कार्यों का भार भी बढ़ रहा है। भूकम्प सक्रिय क्षेत्र तो यह है ही। सेवानिवृत्त मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री से पहले एक विशेषज्ञ इंजीनियर थे। महाआपदा के बाद सितम्बर 2013 में जब कांग्रेस की राज्य सरकार ने 'केदारनाथ विकास प्राधिकरण' बनाने की मंशा जाहिर की तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि 2008 में उनकी सरकार ने केदारनाथ, बदरीनाथ के आसपास निर्माणों पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।

जरूरत यह भी है कि मंदाकिनी नदी के 'फ्लड-जोन' से छेड़छाड़ न हो। यह हिम-पोषित नदी है। दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में गिरी बर्फ इसके लिये महत्वपूर्ण होती है। इसे बरसात, हिमनद और पिघलती बर्फ सभी से पानी मिलता है, किन्तु इसमें 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट' से जोखिम भी पैदा हो रहे हैं।

उत्तराखंड में ग्लेशियरों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह गया है। पगडंडी मार्गों पर हिमस्खलन का जोखिम हर साल बढ़ रहा है। लगभग हर साल ही पुराने पैदल मार्ग को चालू करने की तैयारियों के साथ मार्ग के हिमस्खलनों से सतर्क रहने की आधिकारिक चेतावनी भी आ जाती

है। ऐसी चेतावनियों से कहीं श्रध्दालुओं की आमद कम न हो जाये, इसलिये लोग राहों पर हिमनदों के टुकड़ों के जोखिमों को अब सामान्य भी कहने लगे हैं, किन्तु तथ्य है कि ग्लेशियरों के टूटने की ही तरह ग्लेशियरों का फिसलकर बस्तियों व मोटर मार्गों या ट्रैकिंग राहों में आकर जान-माल का नुकसान करना पूरे भारत में बढ़ा है। मार्च 2021 में पिथौरागढ़ में ही दारमा घाटी में ऐसा हो चुका है।

चार अप्रैल 2023 को उत्तरपूर्वी सिक्किम में जवाहरलाल नेहरू हाइवे पर, जो राजधानी गंगटोक व चीन सीमा पर स्थित नाथूला दर्रे व लोकप्रिय पर्यटन स्थल नाथूला को भी जोड़ता है, सुबह ग्यारह बजे पहुंचे ग्लेशियर ने 35 पर्यटकों व उनके वाहनों को चपेट में ले लिया था और सात पर्यटकों की मृत्यु हो गई थी। जलवायु बदलाव के कारण आज ऊंचाइयों में भी हिमपातों की जगह बरसात हो रही है। जून 2013 की आपदा की बात करें तो उत्तराखंड के संदर्भ में वह शुरुआती मानसून ही था। केदारधाम जैसे हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हेलीकोप्टरों की उड़ानों व भूकम्पकीय झटकों से ताजी बर्फ के फिसलाव व टूटन का खतरा तो रहेगा ही।

केदारघाटी में जगह-जगह सड़कों पर भूस्खलन ही नहीं, भू-धंसाव, मलवा फिसलाव व भू-कटाव के जोन भी बने हैं। जुलाई-अगस्त में ये काफी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में बंद रास्तों को खोलने के लिये मलवे को हर बरसात में नदी में इसी तरह उड़ेला जाता रहा तो मंदाकिनी राह बदल सकती है। पहले भी ऐसा हो चुका है। अगस्त 2024 में भीमबली एयरपोर्ट के पास पहाड़ी में हुये भारी भूस्खलन से मंदाकिनी में जलप्रवाह रूक गया था। इससे वहां एक झील ने आकार ले लिया था, हालांकि धीरे-धीरे स्वतः झील से नदी जल के बाहर निकलने से खतरा टल गया था, किन्तु झील टूटने से जान-माल की क्षति न हो इसलिये गौरीकुण्ड से रूद्रप्रयाग तक नदी के किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया था।

उन पहाड़ियों की दरारों में, जिन पर मलवा टिका है, बरसाती पानी के घुसने से फैलाव आ जाता है। दरार के खण्डित भूखण्डों का टूटना तेज हो जाता है। परिणामस्वरूप भूस्खलन व मलवा बिखराव पुनः प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों की राय से बरसाती जल की उचित ड्रैनेज व्यवस्था बनाना जरूरी है। जलवायु बदलाव के कारण शीतकालीन वनाग्नियां पूरे उत्तराखंड की ही तरह केदारनाथ सेंक्चुरी क्षेत्र में भी बढ़ी हैं। केदारनाथ में वन्यजीवों का संवेदी उच्च हिमालयी क्षेत्र लगभग दस हजार वर्ग किलोमीटर्स का है। केदारपुरी के समीप का यह क्षेत्र बचा ही रहना चाहिये, किन्तु व्यवसायिक हवाई मार्गों और अतिशय हवाई उड़ानों को इनके ऊपर से गुजरना पारिस्थितिक जोखिमों को बढा रहा है।

मई 2023 की शुरूआत में दो दिन में तीन हिमस्खलनों से ये मार्ग बाधित रहा था। केदारनाथ पैदल मार्ग से कई-कई फीट मोटी बर्फ को काटकर हटाना पड़ता है। अक्सर इन्हें नीचे खाइयों में ढ़केल दिया जाता है। भैरव व कुबेर ग्लेशियरों के क्षेत्र में ये हिमस्खलन ज्यादा होते हैं और तब यात्रियों को पैदल मार्ग पर न चलने को कहा जाता है। केदारनाथ जैसी जगहों में बादल विस्फोट बड़ी समस्या होती जा रही है। साथ ही नये-नये लैंडस्लाइडस जोन बने हैं इसलिये 'फ्लैश फ्लड्स' में अब ज्यादा नुकसान होगा।

एक मौसम वैज्ञानिक के अनुसार यदि बादल विस्फोटों की चेतावनियां दी भी जा सकें तो उन पर अमल के लिये दो-तीन घंटों का ही समय मिलता है। इसके अलावा पहाड़ी ढलानों में पानी व मलवा के बहाव में तेजी होती है। वर्ष 2013 की केदार आपदा के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चंद सेकेण्डों में ही रामबाड़ा में मकान, आदमी, वाहनों, जानवरों को बाढ़ बहा ले गई थी। जब बरसात में पहाड़ी गदेरे उफनते हैं तो वे भी तबाही मचाते हैं।

2013 की केदार आपदा के बाद 'एनडीएम' की वार्षिक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सुझाव था कि संवेदनशील इलाकों में बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं के 'इनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट' के साथ 'डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट' भी आवश्यक होना चाहिये। 'लैंडस्लाइड्स रिस्क जोन मैंपिंग' भी पूरा करने की बात की गई थी। कमजोर और ढलान वाले इलाकों में सुधार करना चाहिए जिसकी वैज्ञानिक तकनीकें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं। वैज्ञानिक तरीकों से नये मार्गों का निर्माण व पुनरोद्धार किया जाये। तथ्य यही है कि केदारनाथ के निकटस्थ परिवेश के प्रति संवेदित रह कर ही केदारनाथ धाम यात्रा के जोखिम कम होंगे।

(सप्रेस)

वक्रोक्ति

बढ़ते स्क्रीन टाइम के खतरे से अनजान बच्चों का बचपन

बाल मुकुन्द ओझा

लेखक पत्रकार हैं।

भारत में बच्चों को मोबाइल और टीवी देखने की पूरी आज़ादी है। यहाँ उम्र की कोई बाधा नहीं है। सच तो यह है भारत में बच्चों का बचपन आभासी दुनिया में खो गया है। बच्चों में ज्यादा स्क्रीन टाइम को लेकर होने वाले दुष्परिणामों से स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार देशवासियों को सचेत कर रहे है। अब एम्स की एक स्टडी रिपोर्ट में भी इस खतरे से सचेत किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानि एम्स की एक नई स्टडी में सामने आया है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा स्क्रीन टाइम से 3 साल की उम्र तक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर्स की मानें तो बच्चों की कम उम्र में स्क्रीन के अधिक संपर्क में रहने से बच्चों के दिमाग के विकास और सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुका है। स्टडी से पता चला है कि जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा देर के लिए आपके बच्चे को स्क्रीन टाइम दिया, उन बच्चों में ऑटिज्म के साथ कनेक्शन ज्यादा पाया गया है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्क्रीन टाइम कम करना है।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस के मुताबिक 18 महीने से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए। 18 महीने से 6 साल के बच्चों के लिए सीमित और एक्टिव स्क्रीन देने की सलाह दी जाती है। वहीं जब बच्चा 7 साल से ज्यादा हो जाए तो स्क्रीन टाइम को अधिकतम 2 घंटे तक सीमित किया जा सकता है। इसके साथ ही माता पिता को बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रखना जरूरी है। बच्चे क्या देखकर हैं ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों को वही दिखाएं जो उनके लिए सही है। बेहतर होगा कि हम बच्चे से बातें करें, जितना ज्यादा आप बच्चे से बात करेंगे बच्चे का विकास बेहतर होगा।

दरअसल, बच्चों के लिए मोबाइल फोन और टीवी का आकर्षण अब आम बात हो गई है। अभिभावक भी अपने

काम के चक्कर में बच्चों को मोबाइल फोन देकर या टीवी के सामने बैठा देते हैं। इसका बच्चों पर बहुत खराब असर पड़ता है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम आंखों की रोशनी, नींद की समस्याओं और मोटापे का कारण बन सकता है। स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने से बच्चों के सोशल स्किल कमजोर हो सकते हैं। सोशल मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से बच्चे अवास्तविक अपेक्षाएं पाल सकते हैं।

स्क्रीन टाइम ज्यादा होने का सबसे पहला असर बच्चों की आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है। स्क्रीन को नजदीक और एकटक देखने से आंखें ड्राई होने लगती हैं यही हालात रहने पर आंखों की रोशनी कम होने लगती है। मोबाइल बच्चों का दोस्त है या दुश्मन। बिना विलंब किए अभिभावकों को इस पर गहनता से मंथन की जरुरत है। आजकल मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है। इस तरह के एडिक्शन से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं और ऐसे में बच्चे कोई न कोई गलत कदम उठा लेते हैं। आजकल के बच्चे इंटरनेट लवर हो गए हैं। इनका बचपन रचनात्मक कार्यों की जगह डेटा के जंगल में गुम हो रहा है। पिछले कई सालों में सूचना तकनीक ने जिस तरह से तरक्की की है, इसने मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है बल्कि एक तरह से इसने जीवनशैली को ही बदल डाला है। बच्चे और युवा एक पल भी स्मार्टफोन से खुद को अलग रखना गंवारा नहीं समझते। इनमें हर समय एक तरह का नशा सा सवार रहता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे इंटरनेट एडिक्शन डिस्ऑर्डर कहा गया है।

देश में इंटरनेट के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल में बचपन खोता जा रहा है जिसकी परवाह न सरकार को है और न ही समाज इससे चिंतित है। ऐसा लगता है जैसे गैर जरुरी मुद्दे हम पर हावी होते जारहे है और वास्तविक समस्याओं से हम अपना मुंह मोड़ रहे है। यदि यह यूँ ही चलता रहा तो हम बचपन को बर्बादी की कगार पर पहुंचा देंगे। देश के साथ यह एक बड़ी नाइंसाफी होगी जिसकी कल्पना भी हमें नहीं है। जब से इंटरनेट हमारे जीवन में आया है तबसे बच्चे से बुजुर्ग तक आभासी दुनियां में खो गए है। हम यहाँ बचपन की बात करना चाहते है। देखा जाता है पांच साल का बच्चा भी आँख खोलते ही मोबाइल पर लपकता है। पहले बड़े इसे अपने काम के लिए करते थे। अब बच्चे भी इंटरनेट के शौकीन होते जा रहे हैं। बाजार ने उनके लिए भी इंटरनेट पर इतना कुछ दे दिया है कि वह पढ़ने के अलावा बहुत कुछ इंटरनेट पर करते रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और समय रहते उनकी ऐसी आदत को पॉजेटिव तरीके से दूर करना चाहिए।

जीवन

कागज़ के आगे बेबस गरीब का सच

एक व्यक्ति अपनी मृत बहन के बैंक खाते में जमा धन निकालने के लिए बैंक पहुंचता है। बैंक कर्मचारी उससे मृत्यु प्रमाणपत्र मांगते हैं, जो कि नियमों के अनुसार आवश्यक है। लेकिन, उसके पास वह दस्तावेज़ नहीं होता। इसके बाद जो दृश्य सामने आता है, वह किसी भी संवेदनशील समाज को भीतर तक झकझोर देता है। वह अपनी बहन के शव को कब्र से खोदकर उसके अवशेष कंधे पर लादकर बैंक पहुंच जाता है, मानो यह साबित करने के लिए कि कागज़ से बड़ी भी कोई सच्चाई होती है।

सोनम लववंशी

(स्वतंत्र लेखिका एवं शोधार्थी)

सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर लिखे आदर्श और जमीनी सच्चाई के बीच की दूरी अक्सर इतनी लंबी हो जाती है कि वहां तक पहुंचते-पहुंचते इंसान की उम्मीद ही थक जाती है। कागज़ों में व्यवस्थित दिखने वाली हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, व्यवहार में कई बार सबसे कमजोर नागरिक के लिए सबसे कठिन परीक्षा बन जाती है। और जब यह परीक्षा किसी गरीब, अशिक्षित या हाशिए पर खड़े व्यक्ति के सामने आती है, तो वह केवल एक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि वह उसकी गरिमा, अस्तित्व और आत्मसम्मान की लड़ाई बन जाती है। ओडिशा के क्योंझर जिले से सामने आई घटना इसी विडंबना का एक तीखा और असहज उदाहरण है। एक व्यक्ति अपनी मृत बहन के बैंक खाते में जमा धन निकालने के लिए बैंक पहुंचता है। बैंक कर्मचारी उससे मृत्यु प्रमाणपत्र मांगते हैं। जो कि नियमों के अनुसार आवश्यक है। लेकिन, उसके पास वह दस्तावेज़ नहीं होता। इसके बाद जो दृश्य सामने आता है, वह किसी भी संवेदनशील समाज को भीतर तक झकझोर देता है। वह अपनी बहन के शव को कब्र से खोदकर उसके अवशेष कंधे पर लादकर बैंक पहुंच जाता है, मानो यह साबित करने के लिए कि कागज़ से बड़ी भी कोई सच्चाई होती है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नियमों का अस्तित्व गलत नहीं है। किसी भी वित्तीय संस्था के लिए वैध दस्तावेजों के बिना लेन-देन की अनुमति देना संभव नहीं हो सकता। किंतु प्रश्न यह है कि क्या हर परिस्थिति में नियमों को उसी कठोरता से लागू किया जाना चाहिए, या उनमें मानवीय विवेक और संवेदना के लिए भी कुछ स्थान होना चाहिए? भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कानूनन अनिवार्य है और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में मृत्यु पंजीकरण दर 90% से अधिक तक पहुंची है। यह एक सकारात्मक संकेत है, इन सबके बीच यह औसत आंकड़ा उस असमानता को पूरी तरह नहीं दर्शाता, जो विभिन्न राज्यों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में अब भी मौजूद है। वहां एक साधारण प्रमाणपत्र बनवाना भी कई बार जानकारी के अभाव, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण चुनौतीपूर्ण बन जाता है।

इसी तरह, विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों में यह सामने आया है कि बड़ी संख्या में नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए अतिरिक्त प्रयास, अनौपचारिक तरीकों या यहां तक कि रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट यह संकेत देती हैं कि सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में पारदर्शिता और जवाबदेही की चुनौतियां अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। यह केवल भ्रष्टाचार का प्रश्न नहीं है, बल्कि उस भरोसे का भी है, जो नागरिक और व्यवस्था के बीच होना चाहिए। एक समय तक तकनीक को इस समस्या का समाधान माना गया था। 'डिजिटल इंडिया' जैसे

अभियानों ने यह वादा किया कि सेवाएं सरल और सुलभ होंगी। इंटरनेट और डिजिटल उपयोग से जुड़े अध्ययनों, जैसे इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्टें, यह दर्शाती हैं कि इंटरनेट उपयोग में तेज़ी से वृद्धि हुई है। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और सेवाओं के प्रभावी उपयोग में अभी भी अंतर बना हुआ है। इसका परिणाम यह होता है कि ऑनलाइन सुविधाएं होने के बावजूद वे हर जरूरतमंद व्यक्ति तक समान रूप से नहीं पहुंच पातीं। नीतिगत स्तर पर भी यह स्वीकार किया गया है कि देश के एक हिस्से के पास अभी भी आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ण उपलब्धता नहीं है।

नीति आयोग और अन्य नीति संस्थानों की रिपोर्ट इस ओर संकेत करती हैं कि प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण गरीबों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को पहचान और प्रमाणपत्र से जुड़ी प्रक्रियाओं में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समस्या केवल कागजों की नहीं, बल्कि उस पहचान की है, जो उन्हें व्यवस्था के भीतर अधिकार दिलाती है। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि पूरी सरकारी व्यवस्था असंवेदनशील है। पिछले वर्षों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के कई प्रयास हुए हैं। फिर भी यह उतना ही सच है कि इन सुधारों का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। यही असमानता उस खाई को जन्म देती है, जहां एक व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए असामान्य और पीड़ादायक रास्ता चुनना पड़ता है।

क्योंझर की यह घटना केवल एक विचलित कर देने वाली खबर नहीं है; यह एक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी नीतियां वास्तव में उन लोगों तक पहुंच रही हैं, जिनके लिए वे बनाई गई हैं। क्या हमने प्रक्रियाओं को इतना सरल और मानवीय बनाया है कि कोई भी नागरिक बिनाभय, भ्रम और अपमान के उनका उपयोग कर सके? समाधान स्पष्ट हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में गंभीरता की आवश्यकता है। प्रक्रियाओं को और सरल बनाना, स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना, और सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक तंत्र में संवेदनशीलता को बढ़ावा देना अनिवार्य है। तकनीक का विस्तार जरूरी है, लेकिन उसके साथ मानवीय सहयोग और मार्गदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अंततः, किसी भी व्यवस्था की वास्तविक कसौटी उसके नियम नहीं, बल्कि उन नियमों का प्रभाव होता है। यदि एक गरीब व्यक्ति को अपनी बहन की मृत्यु साबित करने के लिए उसके अवशेष उठाने पड़े, तो यह केवल उसकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, यह हमारी सामूहिक विफलता का संकेत है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम कैसी व्यवस्था चाहते हैं। एक ऐसी, जो कागज़ों को सर्वोपरि मानती हो, या एक ऐसी, जो इंसान की सच्चाई और उसकी गरिमा को समझते हुए कागज़ों को अर्थ देती हो। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसके कानूनों से नहीं, उसकी संवेदनशीलता से होती है।

थैलेसीमिया पीड़ित मासूमों के लिए पैदल चला बैतूल

थैलेसीमिया पीड़ित मासूमों को लिया गोद

बैतूल। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर मां शारदा सहायता समिति, थैलेसीमिया जनजागरण समिति मप्र के बैनर तले सुबह 7 बजे कारगिल चौक से राष्ट्रगान और थैलेसीमिया उन्मूलन हस्ताक्षर अभियान के साथ जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बैतूल थैलेसीमिया की मुक्ति हेतु पैदल चला। कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र बिहारिया ने बताया कि इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष अशोक रघुवंशी, भरत सूर्यवंशी,रामनारायण शुक्ला पुरुष वर्ग में व महिला वर्ग में कार्यक्रम अध्यक्ष प्रमिला धोत्रे, सरिता राठौड़, पूनम धोटे, साक्षी शर्मा थी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर स्मिता राठी,पूर्व नगरपालिका

अध्यक्ष आनंद प्रजापति, समाजसेवी अतीत पवार, संजय शुक्ला, पार्षद नंदिनी तिवारी, अनिल राठौर, धीरज हिरानी, मुकेश गुप्ता, करण प्रजापति, बबलू दुबे, सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश घोरे, डॉक्टर अंकिता सीते, रेड क्रॉस के चेयरमेन डॉ. अरुण जयसिंहपुरे, संस्था के अध्यक्ष हिमांशु सोनी, महिला अध्यक्ष हेमासिंह चौहान, निमिषा शुक्ला, सुषमा सोनी, कल्पना माझी,रुकमणि सुनारे, दीपा मालवीय, सोनम मिश्रा, बाली चौहान उपस्थित थे। थैलेसीमिया पीड़ित मासूमों को उपहार भेंट इस अवसर पर थैलेसीमिया पीड़ित मासूमों को राठी हॉस्पिटल की और से गर्मी में ठंडे पानी हेतु पानी बाटलो का वितरण किया गया। साथ ही फल, चॉकलेट, तरबूज, खेल सामग्री भेंट की गई, उनकी पीड़ा को मंच से सुना गया।

थैलेसीमिया उन्मूलन की ली शपथ.....

इस अवसर पर सभी ने थैलेसीमिया उन्मूलन की शपथ भी ली। मासूमों को रक्तदान के लिए लिया गोद इस अवसर पर इन मासूमों को सुषमा सोनी,डॉ स्मिता राठी,संस्था के सदस्यों ने रक्त एवं आर्थिक मदद के लिए गोद भी लिया। इस बीमारी के बारे में बताते हुए थैलेसीमिया पीड़ित अंकित पाल की मां रो पड़ी उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटियां इस बीमारी से काल कवलित हो गई। इन मासूमों के लिए रक्तदान करने वाले रक्तवीरो को किया सम्मानित इन मासूमों के लिए हमेशा रक्तदान करने वाले उमेश दाभाडे, मोइज फकरी, खोजेंम खान, प्रकाश बंजारे,प्रेम वर्मा, महेंद्र प्रजापति, डॉ सागर बिंझाड़े, प्रीतमसिंह मरकाम, सुनील पाल,प्रिया पाल,दीपा मालवीय, निमिषा शुक्ला को रक्त क्रांति अवार्ड दिया गया।

भाजपा सरकार किसान, युवा और महिलाओं के मुद्दों से भाग रही है : कांग्रेस

बर्राढाना अग्निकांड, महिला सुरक्षा और बंद स्कूलों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

बैतूल। जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में नव नियुक्त जिला प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया प्रभारियों का परिचय कराया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर किसान, युवा, महिला और आमजन

विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस लगातार किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों की आवाज उठाती रहेगी। जिला कांग्रेस कमेटी ने लवलेश बब्बा राठौर और विजय पारधी को जिला कांग्रेस प्रवक्ता, अतुल शर्मा आईटी सेल जिला अध्यक्ष तथा उमाकांत शर्मा और अनूप जैसवाल को सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करना और जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाना है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं होने की बात कही गई थी। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले वर्ष 2017 के मंदसौर गोलीकांड को याद करना चाहिए, जहां भाजपा सरकार के दौरान छह किसानों की गोली लगने से मौत हुई थी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों के प्रति संवेदनशीलता का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने हमेशा किसानों की आवाज दबाने का काम किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 70 हजार करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया था। वहीं वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहली ही कैबिनेट बैठक में किसानों के दो लाख रुपए तक के कर्जमाफी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन भाजपा ने सरकार गिराकर इस प्रक्रिया को रोक दिया।

किसान खाद, बीज और उपज के उचित मूल्य के लिए परेशान- कांग्रेस ने वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पुराने वादे याद दिलाते हुए कहा कि भाजपा ने किसानों से कर्जमाफी, आय बढ़ाने और कृषि व्यवस्था सुधारने के वादे किए थे, लेकिन आज किसान खाद, बीज और उपज के उचित मूल्य के लिए परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब देशभर में करोड़ों लोग आईपीएल मैच देखते हैं तब सर्वर डाउन नहीं होता, लेकिन किसानों के पंजीयन के समय पोर्टल बंद हो जाता है। नरवाई जलाने पर किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार पहले इसका वैकल्पिक समाधान उपलब्ध कराए, उसके बाद दंडात्मक कार्रवाई करे।

घोड़ाडोंगरी के ग्राम डुल्हारा और सिवनपाट में खनिज विभाग ने अवैध भंडारित कोयले को किया जप्त

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम डुल्हारा एवं सिवनपाट में स्थित तवा नदी क्षेत्रों में खनिज कोयले के अवैध उत्खनन की सूचना प्राप्त होने पर खनिज अमले द्वारा निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान नदी क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को खनिज कोयला का उत्खनन, परिवहन करते नहीं पाया गया, किन्तु उक्त क्षेत्र में एक स्थान पर लगभग 01 ट्राली कोयला अवैध रूप से लावारिस

पाया गया, जिसे जप्त कर पुलिस थाना चोपना की अभिरक्षा में रखा गया है। जिस स्थान पर लावारिस कोयला पाया गया उस क्षेत्र के आसपास किसी प्रकार के कोयला खनन के निशान, गड्ढे नहीं होना पाया गया। साथ ही निरीक्षण दल द्वारा ग्राम डुल्हारा एवं सिवनपाट के क्षेत्रों में पूर्व से बने गड्ढे बंद पाये गये है, जिसमें कोयले के उत्खनन के अवशेष एवं चिन्ह, निशान नहीं पाये गये। उक्त क्षेत्र में खनिज कोयला के अवैध उत्खनन के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, किन्तु उनसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। गौरतलब है कि पूर्व में भी खनिज विभाग द्वारा उक्त स्थल से खनिज कोयला के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम के लिए कठोर कार्यवाही की गई थी। वर्तमान में भी उक्त क्षेत्र के आसपास खनिज कोयला के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाकर सतत निगरानी रखी जा रही है।

जनगणना 2027 कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगणक एवं पर्यवेक्षक सम्मानित

बैतूल। जनगणना 2027 के अंतर्गत तहसील आमला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनगणना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले समस्त पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को तहसील कार्यालय सभाकक्ष आमला में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त जनगणना चार्ज अधिकारी (ग्रामीण) आमला श्रीमती रिचा कौरव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं जनगणना चार्ज अधिकारी (शहरी) आमला नितीन बिजवें तथा जनगणना शाखा प्रभारी (ग्रामीण) आमला दिलीप सोनुपरे द्वारा सभी पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई। अनुविभागीय अधिकारी रा. एवं अनु.जनगणना अधिकारी आमला ने बताया कि जनगणना 2027 के लिए तहसील आमला ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत 277 एचएलबी में नियुक्त पर्यवेक्षक एवं उनके प्रगणकों द्वारा अपने-अपने एचएलबी में घरों घरों जाकर प्रत्येक घरों की जनगणना का कार्य प्रारंभ है। जिसमें आमला ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे प्रगणक जिन्हें आवंटित एचएलबी में कुल घरों की संख्या 170 से अधिक होने पर भी उनके द्वारा जनगणना सर्वे का कार्य 5 से 6 दिवस में पूर्ण कर लिया है। जिसमें सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती संगीता पवार एवं प्राथमिक शिक्षक मन्तुलाल कवड़े द्वारा यह कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किया गया। साथ ही इनके द्वारा अतिरिक्त अन्य 15 प्रगणकों के द्वारा जनगणना सर्वे के कार्य को पूर्ण किया गया तथा पर्यवेक्षकों में उच्च माध्यमिक शिक्षक श्रीमती रिचा साहू एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक मनोज बुवाड़े द्वारा अपने प्रगणकों को कार्य में अच्छा मार्गदर्शन देकर अपने अधीनस्थ एचएलबी में 3-3 एचएलबी का कार्य पूर्ण करवाया गया एवं शहरी क्षेत्र में कुल 41 एचएलबी में सर्वप्रथम न.पा. कर्मचारी रोशन कवडे एवं पर्यवेक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रतीक कुमार धुर्वे के द्वारा जनगणना सर्वे कार्य को पूर्ण किया गया।

जनगणना 2027 : मकान सूचीकरण के फील्ड कार्य का वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया जायजा

बैतूल। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण 'मकान सूचीकरण एवं आवास गणना' के कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को सहायक निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय भोपाल श्रीमती अनिमिका जैन, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार गौतम, जिला प्रभारी श्री भरत गौर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अभिजीत सिंह द्वारा ग्रामीण चार्ज के ग्राम चिखलार एवं नगरीय चार्ज नगर पालिका बैतूल के महावीर वार्ड फील्ड में पहुंचकर सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा भरी जा रही जानकारी की शुद्धता की जांच की। जिला योजना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी जिला बैतूल श्री नरेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि जिले के विभिन्न वार्डों और ग्रामों का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रगणकों द्वारा मकानों पर डाले जा रहे नंबरों और एचएलओ ऐप में दर्ज की जा रही जानकारी का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने फील्ड स्टाफ को एचएलओ मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा प्रविष्टि करने के संबंध में आवश्यक तकनीकी दिशा-निर्देश दिए। साथ ही किसी भी प्रकार की त्रुटि न करने की सख्त हिदायत दी। फील्ड में कार्यरत टीम को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाए।

लोक अदालत में सहयोग के लिए अधिवक्ताओं के साथ बैठक का आयोजन

बैतूल। 9 मई को वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन पूरे जिले में किया जाएगा। अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा व निराकरण में सहयोग एवं चर्चा के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश चन्द्र थपलियाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला अधिवक्ता संघ सभागार में समस्त अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चन्द्र थपलियाल ने बताया कि लोक अदालत से न केवल प्रकरण का निराकरण होता है, अपितु इससे दोनों पक्षों की आपसी वैमनस्यता खत्म हो जाती है। पक्षकारों की कोर्ट फीस की प्रक्रिया भी आसान हुई है। संघ के समस्त अधिवक्ताओं से विगत लोक अदालतों में निरंतर सहयोग प्राप्त हुआ है और इसी प्रकार वर्तमान लोक अदालत में भी सहयोग अपेक्षित है। नेशनल लोक अदालत प्रभारी अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश रईस खान द्वारा भी समस्त अधिवक्ताओं से न्यायदान में सहयोग की अपेक्षा की गई। प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय शिवबालक साहू, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अशोक वर्मा तथा जिला प्राधिकरण सचिव श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा भी लोक अदालत का पक्षकारों व अधिवक्ताओं के लिए महत्व बताते हुए इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा कराने की सभी अधिवक्ताओं से अपेक्षा की गई। इस अवसर पर अन्य समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण तथा न्यायिक मजिस्ट्रेटगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी, समस्त अधिवक्ता उपस्थित रहें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा पूरे जिले के लिए कुल 27 खण्डपीठों का गठन किया गया था।

टीटीई ने बुजुर्ग महिला के मुंह पर मुक्का मारा

बुजुर्ग महिला नहीं मानी तो पीट-पीटकर दांत तोड़ दिए

भोपाल। भोपाल में कुशीनगर एक्सप्रेस में 75 साल की बुजुर्ग महिला से टीटीई ने बेरहमी से मारपीट कर दी। आरोपी ने महिला के मुंह पर घूंसा मारकर उसके दांत तोड़ दिए। दरअसल, नर्मदापुरम से वह भोपाल की यात्रा करने के लिए स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन चलने के लिए तैयार हुई और बुजुर्ग सामने खड़े एसी कोच में चढ़ गई। एसी कोच में चढ़ने से टीसी भड़क गया। बुजुर्ग ने उसे कहा कि वह धीरे धीरे स्लीपर कोच में जा रही है। इस पर वह कहने लगा कि जल्दी निकलो। उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्ग हूं और जल्दी जल्दी नहीं चल सकूंगी। इस पर वह भड़क गया और हाथ मोड़कर घूंसा मार दिया। घूंसा लगने से बुजुर्ग महिला का दांत टूट गया। रानी

कमलापति स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने के बाद बुजुर्ग महिला ने जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने टीटीई नदीम खान पर मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। पूरा घटनाक्रम 6 मई का है, जबकि शुक्रवार को आरोपी नदीम की गिरफ्तारी कर ली गई।

तत्काल निर्देश नहीं मानने से भड़का नदीम- जीआरपी रानी कमलापति थाने के प्रभारी एमएस सोमवंशी ने बताया कि सुशीला देवी(75) डी-6 पूर्वी रेलवे कॉलोनी भोपाल में रहती हैं। 6 मई को वह

● एसी कोच में चढ़ने से नाराज था,तत्काल उतरने कहा

कुशीनगर एक्स से नर्मदापुरम से भोपाल की यात्रा कर रही थी। ट्रेन नर्मदापुरम से चलने को तैयार हो गई। ट्रेन छूटने के डर से सुशीला देवी एसी कोच में चढ़ गई। ट्रेन में सवार टीटीई नदीम खान ने महिला को तत्काल बोगी से उतरने का निर्देश दिया। सुशीला देवी ने कहा कि मेरी उम्र 75 साल है। मैं धीरे धीरे ही चल सकूंगी। यह बात सुनकर नदीम खान भड़क गया। उसने हाथ पकड़कर मोड़ दिया। विरोध करने पर उसने मुंह का घूंसा मारा था। जिससे दांत टूट गया और खून निकलने लगा। कुछ लोगों ने बीच बचाव करते हुए टीटीई से बचाया। बाद में उन्होंने अपने बेटे को घटना की जानकारी दी। बेटा ने जीआरपी को शिकायत की। जीआरपी की टीम सुशीला देवी और टीटीई को लेकर थाने पहुंची। वहां टीटीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला का बेटा भी टीटीई है।

सागर में कुदरत का कहर पानी की तरह बही आग

भोपाल। सागर में बुधवार शाम मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं के कारण जहां ग्रामीण इलाकों में कई घरों की चद्दरें उड़ गईं, वहीं आगजनी की घटनाओं से लोगों में दहशत फैल गई। जरूवाखेड़ा इलाके में जंगल और खेतों में लगी आग आबादी तक पहुंच गई। जरूवाखेड़ा में बुधवार शाम आए तूफान ने हालात बिगाड़ दिए। तेज हवाओं के चलते हाई स्कूल ग्राउंड के पास खेतों में लगी आग अचानक विकराल हो गई। हवा का रुख घनी आबादी की ओर होने से आग की लपटें रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगीं, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और पानी के टैंकरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

सड़क पर गिरे जलते अंगारे, यातायात प्रभावित- सेमरा पुल के पास खेतों में लगी आग सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ों तक पहुंच गई। तेज हवा के कारण जलते हुए अंगारे सड़क पर गिरने लगे, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया। सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी। वहीं सागर शहर के मुख्य बस स्टैंड स्थित एक होटल में भी आग लग गई। आग लगने के समय होटल के अंदर कई लोग खाना खा रहे थे। देखते ही देखते पूरा होटल धुएं से भर गया और कई लोग अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम और स्थानीय युवाओं ने साहस दिखाते हुए होटल की खिड़कियों के कांच तोड़े और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

मंत्री राजपूत से कुश समाज कल्याण के अध्यक्ष प्रभुदयाल की सौजन्य भेंट

समाज उत्थान, शिक्षा, युवाओं के भविष्य और संगठन विस्तार को लेकर हुई विस्तृत चर्चा

सागर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निज निवास 'मातेश्वरी' पर मध्य प्रदेश कुश समाज कल्याण के नव नियुक्त अध्यक्ष प्रभुदयाल पटेल ने अपने साथियों सहित सौजन्य भेंट कर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समाज हित, संगठन सशक्तिकरण तथा युवाओं के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। भेंट के दौरान प्रभुदयाल पटेल ने मंत्री श्री राजपूत को संगठन की भावी योजनाओं, समाज के उत्थान हेतु किए जा रहे प्रयासों तथा प्रदेशभर में समाज को संगठित करने की कार्ययोजना से अवगत कराया। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक एकता और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

समाज की एकता और शिक्षा पर दिया विशेष जोर- मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति का आधार शिक्षा, संगठन और सामाजिक समरसता होती है। समाज के युवाओं को आधुनिक शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और रोजगारोन्मुखी अवसरों से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

मंत्री ने समाज के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के उत्थान के लिए सकारात्मक पहल लगातार जारी है।

उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से समाज में जागरूकता बढ़ती है तथा नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मंत्री श्री राजपूत ने नव नियुक्त अध्यक्ष प्रभुदयाल पटेल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

समाज हित के मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा- बैठक के दौरान समाज के विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, युवाओं के कौशल विकास, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन, संगठन विस्तार तथा समाज के जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।

श्री पटेल ने कहा कि समाज के सहयोग और वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन से संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा तथा समाज के हर वर्ग को साथ लेकर कार्य किया जाएगा।

कार्यकर्ताओं और समाजजनों में उत्साह- मंत्री निवास पर हुई इस सौजन्य भेंट के दौरान समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। उपस्थित लोगों ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समाज हितैषी दृष्टिकोण और सहयोगात्मक भावना की सराहना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजन एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

संकलखेड़ा उपार्जन केंद्र का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

विदिशा (निप्र)। विदिशा एसडीएम श्री क्षितिज शर्मा द्वारा संकलखेड़ा स्थित उपार्जन केंद्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का आज निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र पर किसानों से की जा रही उपज खरीदी की प्रक्रिया, तौल व्यवस्था एवं रिकॉर्ड संधारण का जायजा लिया। एसडीएम श्री शर्मा ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि उपार्जन कार्य पारदर्शिता एवं सुचारु रूप से संचालित किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को समय पर टोकन, तौल एवं भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। निरीक्षण अवसर पर उन्होंने केंद्र पर साफ-सफाई, पेयजल, छाया एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की तथा आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए। एसडीएम ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानीं और मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

सीएमएचओ ने सिरोंज जन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश

विदिशा (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार द्वारा सिरोंज स्थित जन चिकित्सालय का आज औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया गया। डॉ. कुमार ने अस्पताल परिसर की साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया तथा चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने डायलिसिस सेवा प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त कक्ष का चयन करने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त, लेबर रूम एवं ब्लड स्टोरेज यूनिट में बेहतर तापमान नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एयर कंडीशनर (एसी) की व्यवस्था करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संचालित की जाएं।

मिट्टी एवं गिट्टी का अवैध परिवहन करते 02 वाहन जप्त जिला प्रशासन की कार्यवाही जारी

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले में रेत एवं अन्य गौण खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, ओवरलोड खनिज परिवहन एवं बिना ढके रेत का परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध सतत् कार्यवाही की जा रही है। जिसके अनुक्रम में खनिज विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मोहासा, तहसील-माखननगर से 01 डम्पर क्रमांक-एमपी66एच1520 को मिट्टी खनिज के अवैध उत्खनन / भण्डारण में लिप्त पाये जाने पर जप्त कर पुलिस थाना माखननगर की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है एवं ग्राम-सहेली, तह0-इटारसी से 01 डम्पर क्रमांक-आरजे17जीबी0670 को गिट्टी खनिज का ओवरलोड परिवहन करते पाये जाने पर जप्त कर पुलिस थाना केसला की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है। साथ ही रेत के वाहनों की जाँचकर रेत का परिवहन ढककर किए जाने एवं नियंत्रित गति से वाहन चलाए जाने के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। उक्त जप्त वाहनों के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

शाहपुर में गौवंश दुर्घटना, घायल पशुओं का उपचार जारी

बैतूल (निप्र)। जिले के शाहपुर क्षेत्र में गौवंश के साथ हुई दुर्घटना के संबंध में उप संचालक पशुपालन श्री सुरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 2 पशु मृत पाए गए, जबकि 4 पशु गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। घायलों का मौके पर ही उपचार कराया गया है तथा उनके निरंतर फॉलोअप उपचार के लिए संबंधित पशु चिकित्सक को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कराकर उनके सैंपल लैबोरेट्री जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। घटनास्थल पर मौजूद समाजसेवियों एवं ग्रामीण पशुपालकों से भी चर्चा की गई तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।प्रशासन द्वारा पूरे मामले की निगरानी की जा रही है। डॉग स्क्वायड टीम ने भी मौके पर पहुंचकर अन्य बम बरामद किए गए। साथ ही सैंपल्स को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए भी डायग्नोसिस के लिए भेजा गया है।

श्रमिकों को मिला बकाया भुगतान, त्वरित कार्रवाई से 75 हजार रुपये दिलाए गए

नर्मदापुरम (निप्र)। जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के तहत श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। श्रम कार्यालय में प्राप्त एक शिकायत में आवेदक प्रेमचंद्र सहित अन्य 5 श्रमिकों (निवासी ग्राम कचनरवा, तहसील रावतसगंज, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश) द्वारा मोहासा (तहसील माखननगर) स्थित ग्रू सोलर कंपनी में मजदूरी कार्य के बकाया भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रम निरीक्षक सुश्री सरिता साहू द्वारा कार्यालय स्तर पर दोनों पक्षों के मध्य बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान ठेकेदार संस्था पालीवाल कंस्ट्रक्शन के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को कुल 75,000 रुपये की बकाया मजदूरी का भुगतान कराया गया। साथ ही श्रमिकों को 3,000 रुपये की वापसी यात्रा राशि भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई गई तथा उनका पंजीयन उत्तर प्रदेश भवन निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत कराया गया। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया।

महिलाओं की आजीविका गतिविधियों की सराहना, मार्केट लिंकेज बढ़ाने के दिए निर्देश

कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने ग्राम तोरणवाडा में स्व-सहायता समूह की महिलाओं से की चर्चा

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बुधवार को आमला भ्रमण के दौरान ग्राम तोरणवाडा पहुंचकर स्व-सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की तथा समूहों द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली। समूह की महिलाओं ने कलेक्टर डॉ सोनवणे को बताया कि ग्राम में कुल 22 स्व-सहायता समूह संचालित हैं, जिनसे 285 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाएं बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई कार्य, टेंट व्यवसाय, ऑटो वाहन संचालन एवं किराना दुकान जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि समूह की अधिकांश सदस्य प्रतिमाह 10 से 15 हजार रुपए तक की आय अर्जित कर 'लखपति दीदी 'की श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने जिला परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन को समूहों के उत्पादों एवं गतिविधियों के लिए बेहतर मार्केट लिंकेज विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं द्वारा रखी गई आजीविका भवन की मांग के निराकरण के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर पेयजल, राशन वितरण, पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं के लाभ की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

आंगनवाड़ी केंद्र का भी किया निरीक्षण

इसके पूर्व कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने ग्राम तोरणवाडा के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 01 एवं 02 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पोषण ट्रैकर एप, मिशन नींव के अंतर्गत संचालित ईसीसीई गतिविधियों एवं बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। मिशन नींव के तहत संचालित गतिविधियों को देखकर कलेक्टर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे विकासखंड में पहली बार इस प्रकार की गतिविधियां प्रभावी रूप से प्रदर्शित की गई हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों की साफ-सफाई एवं साज-सज्जा की भी सराहना की तथा सैम बच्चों की स्थिति एवं देखभाल की जानकारी प्राप्त की।

देवनगर में 12 मई को आयोजित होगा जिला स्तरीय युवा संगम मेला

रायसेन (निप्र)। जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार 12 मई 2026 को गैरतगंज विकासखण्ड के देवनगर स्थित पीएमश्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय युवा संगम मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वधान में आयोजित यह युवा संगम मेला 12 मई को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक आयोजित होगा। इस युवा संगम मेले के माध्यम से युवाओं को विभिन्न कम्पनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के साथ ही शासन की स्वरोजगारमूलक योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस जिला स्तरीय युवा संगम मेले में नवभारत फर्टीलाइजर भोपाल, भास्कर मण्डीदीप, आईपीएस भोपाल, इंसुलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स मण्डीदीप, यश्यवी ग्रुप मण्डीदीप, सागर मेनिफेक्चर तामोट, होम हेल्प सेंटर रायसेन, हकाई सिकरोटी मण्डीदीप, आर सेठी रायसेन, वोल्वो आयशर वगरोदा, पुखराज प्रा.लि. भोपाल समर्थन ट्रस्ट भोपाल द्वारा विभिन्न पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी।

सीपीआर प्रक्रिया आपात स्थिति सिद्ध होती है जीवन रक्षक प्रक्रिया : कलेक्टर

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, मृत्यु दर में कमी लाने एवं घायलों को समय पर राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनसुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दुर्घटना के बाद सहायता पहुंचने में लगने वाले समय के दौरान आमजन एवं अधिकारियों को प्राथमिक उपचार देने में सक्षम बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा सीपीआर प्रक्रिया का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं जनसुनवाई में आए आवेदकों को सीपीआर देने की विधि विस्तारपूर्वक समझाई गई। साथ ही प्रतिभागियों को डमी के माध्यम से स्वयं अभ्यास कराकर प्रशिक्षण को व्यावहारिक रूप से भी सुदृढ़ किया गया।

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने सीपीआर को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह एक सरल लेकिन प्रभावी जीवन रक्षक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में सही समय पर सीपीआर देने से किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस प्रकार के प्रशिक्षण को गंभीरता से लें और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर मानव जीवन की रक्षा में सहयोग करें।

आरबीएसके योजना से 10 वर्षीय बच्ची खुशी का जन्मजात हृदय रोग का सफल ऑपरेशन हुआ

विदिशा (निप्र)। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जन्मजात बीमारियों के सफल ऑपरेशन कर कई परिवारों के घरों की खुशियां लौट रही हैं। इस योजना का लाभ मिलने से कई बच्चों के चेहरों की मुस्कान वापस लौट रही है।

ऐसे ही एक कहानी है विदिशा जिले की नटेरन तहसील के ग्राम हसनपुर में रहने वाले एक कुशवाहा परिवार की। कुशवाह परिवार के श्री महेंद्र अहिरवार की 10 वर्षीय छोटी पुत्री खुशी का जन्मजात हृदय रोग का सफल ऑपरेशन आरबीएसके योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड की मदद से भोपाल के चिरायु अस्पताल में हुआ है। विदिशा जिले की नटेरन तहसील के हसनपुर ग्राम निवासी श्री महेन्द्र अहिरवार के घर 18

अक्टूबर 2015 को एक पुत्री का जन्म हुआ पूरा परिवार पुत्री को पाकर बहुत खुश था जन्म के बाद कुछ समय गुजर गया बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ्य नहीं लग रही थी अनेक बार डॉक्टर को दिखाया एवं उपचार भी करवाया लेकिन शारीरिक विकास अपेक्षित रूप से नहीं हो पा रहा था एवं शारीरिक दुर्वलता के रहते अन्य समस्याएं होने लगीं थीं। बच्ची खेलते खेलते हांफने लगती थी आरबीएसके टीम ने बच्ची को संज्ञान में लेकर परिवार की कांउसलिंग की, बच्ची को तुरंत उपचार की आवश्यता थी बच्ची माता-पिता को जिला अस्पताल द्वारा चिन्हित हास्पिटलों में जाकर बच्चे का तुरंत ईको करवाने एवं उपचार निर्धारण हेतु भेजा। परिजन अपनी इछा से बच्चे को चिरायु हास्पिटल भोपाल में जांच एवं उपचार हेतु ले गये। हास्पिटल में जांच के उपरांत ज्ञात हुआ कि बच्ची हृदय रोग की समस्या से पीडित है। समस्त तैयारियों के उपरांत 10 अप्रैल 2026 को आयुष्मान योजना अंतर्गत चिरायु हास्पिटल भोपाल में सफल आपरेशन हुआ।

आपरेशन के बाद परिवार बहुत खुश हुआ आज कुशवाह आरबीएसके (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) तहत हुए निशुल्क स्वास्थ्य उपचार से कुशवाह परिवार पूर्ण रूप से संतुष्ट है। समस्त उपचार की प्रक्रिया में आरबीएसके टीम डीईआईसी स्टाफ की विशेष भूमिका रही ऑपरेशन के उपरांत बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ्य है एवं बच्चे का नियमित फालोअप लिया जा रहा है।

जिले में जनगणना कार्य प्रगति की संयुक्त निदेशक ने की समीक्षा

- कोई भी मकान सर्वे से छूटे नहीं - संयुक्त निदेशक श्री पटेल
- संयुक्त निदेशक ने ग्राम थूना कला में जनगणना कार्य का किया निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। गृह विभाग जनगणना कार्य निदेशालय के संयुक्त निदेशक श्री राम अवतार पटेल ने सीहोर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर सीहोर जिले में जनगणना 2027 अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विभिन्न चार्ज क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति, निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धि, प्रगणकों की कार्यप्रणाली तथा फील्ड स्तर पर आ रही समस्याओं एवं चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही कार्य में तेजी लाने, शेष लक्ष्य को समय-सीमा में पूर्ण करने एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा संकलन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि मकान सूचीकरण कार्य में डेटा की शुद्धता एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा सभी प्रविष्टियाँ पूर्णतः सही, स्पष्ट एवं त्रुटि रहित हों। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मकान सर्वे से छूटे नहीं तथा किसी भी प्रकार की डुप्लीकेट प्रविष्टि न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य के दौरान फील्ड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाए। उन्होंने सभी चार्ज अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रगणक एवं पर्यवेक्षक निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करें। साथ ही HLO ऐप में डेटा एंट्री समय पर एवं शुद्धता के साथ अपडेट की जाए, ताकि प्रगति का सही आकलन किया जा सके। बैठक में वर्तमान भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए फील्ड में कार्यरत प्रगणकों, पर्यवेक्षकों एवं अन्य अमले के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि फील्ड स्टाफ को पर्याप्त पेयजल, आवश्यक विश्राम, छायादार स्थानों की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे सुरक्षित वातावरण में कार्य कर सकें और किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। इसके साथ ही, जनगणना कार्य के दौरान आमजन के साथ शालीन, सौम्य एवं सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों का विश्वास अर्जित कर उनसे सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त करना इस कार्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनगणना का कार्य संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ संपादित हो, जिससे शासन को सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो सकें और भविष्य की योजनाओं के निर्माण में इनका प्रभावी उपयोग किया जा सके। कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान संयुक्त कलेक्टर एवं जनगणना प्रभारी श्री जमील खान सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही जनगणना से जुड़े सभी संबंधित अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

केंद्रीय कृषि मंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के भैरूंदा में 10 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर श्री बालागुरू के. और केंद्रीय कृषि मंत्री के निज सचिव श्री प्रवीण सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पहले ही पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर आगमन, निर्गमन, पेयजल, बैरिकेडिंग, पार्किंग, फायर ब्रिगेड, यातायात, बैठक व्यवस्था एवं साफ सफाई सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एएसपी श्रीमती सुनिता रावत ने सभी पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रमों में सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि 10 मई को भैरूंदा में पीएमजीएसवाई - IV बैच एवं पीएमजनमन (वर्ष 2026-27) का शुभारंभ कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का शामिल होना प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान विधायक बुधनी श्री रमाकांत भार्गव, एसडीएम श्री सुधीर कुशवाह, तहसीलदार श्री सौरभ शर्मा, जनपद सीईओ श्री संजय अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मैदान में उतरे खाद्य मंत्री, उपार्जन केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण

उपार्जन केंद्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं- गोविंद सिंह राजपूत

खाद्य मंत्री ने किसानों से किया सीधा संवाद, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, तुलाई और खरीदी व्यवस्था भी जांची

रायसेन (निप्र)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रदेश के खाद्यए नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को भोपाल से सागर जाते समय अचानक रायसेन जिले के सेहतगंज स्थित उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मंत्री स्वयं मैदान में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए तुलाई,

खरीदी एवं अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। खाद्य मंत्री ने मौके पर वारदाने का वजन कराया और भरे बोरे के गेहू का वजन कराया। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री राजपूत ने उपार्जन केंद्र पर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की तथा ऑटो कनेक्टिविटी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीदी के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने और तुलाई प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मौके पर कार्य में थोड़ी शिथिलता पाए जाने पर खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने संबंधित सर्वे कर्मचारियों वसुंधरा गौर और शिवराज लोधी को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने किसानों से भी सीधा संवाद किया। रंगपुर के किसान किशन गोपी और कैलाश यादव ने बताया कि उन्हें उपार्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है तथा उनकी फसल की तुलाई समय पर हो रही है। किसानों ने उपार्जन केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं को संतोषजनक बताया। मंत्री श्री राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और गेहूं उपार्जन एवं तुलाई का कार्य समयबद्ध एवं सुचारू रूप से संपन्न किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। खाद्य मंत्री श्री राजपूत इसके बाद रतनपुर के प्रेम वेयर हाउस पहुंचे। वहां पर शेख आबिद सहित कई किसानों ने बताया कि उन्हें उपार्जन में कोई परेशानी नहीं हो रही है। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, श्री जिला आपूर्ति अधिकारी राजू कातुलकर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

राइट क्लिक

क्या तमिलों का द्रविड़ राजनीति से मोहभंग होने लगा है?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में इस चुनाव में धूमकेतु की तरह उभरे नेता और लोकप्रिय अभिनेता फिल्म अभिनेता जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ थलपति विजय तथा उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझघम (टीवीके) अंततः सरकार बनाने लायक समर्थन जुटाने में सफल हो गई हो, लेकिन द्रविड़ राजनीति की धुरी रहे इस राज्य में विजय और टीवीके का उदय क्या इस राज्य में पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के अस्ताचल की शुरूआत है? या विजय के रूप में यही राजनीति एक नया चेहरा अख्तियार करेगी? क्या तमिल मतदाता का द्रविड़ राजनीति के मूल तत्वों जैसे कि सनातन हिंदू विरोध, हिंदी विरोध, आर्य और संस्कृत विरोध, ब्राह्मण विरोध, नास्तिक सेक्युलरवाद, तमिल भाषा, संस्कृति को लेकर अति संवदेनशीलता तथा जाति आधारित आरक्षण के प्रबल समर्थन के आग्रह से मोह भंग हो गया है अथवा विजय का उभार तमिल पहचान के हिंदुत्व की व्यापक छतरी में स्वीकार का नया और शुरूआती चरण है? क्या तमिलों की युवा पीढ़ी अब अपने राज्य और संस्कृति को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आग्रही है? और क्या ऐसे में वहां भाजपा के पैर फैलाने की गुंजाइश बन सकती है? ये वो तमाम सवाल हैं, जो इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नतीजों से उभर रहे हैं।

तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन की शुरूआत बीसवीं सदी की शुरूआत में सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आग्रह, ब्राह्मणों के वर्चस्व और हिंदी थोपे जाने के विरोध में हुई थी। इसने पिछड़ी और छोटी जातियों को एकजुट किया। परिणामस्वरूप 1967 के विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुन्नेत्र कषघम (डीएमके) नेता अन्ना दुराई के नेतृत्व में पहली बार डीएमके की सरकार बनी। अन्ना दुराई सर्वमान्य नेता थे, लेकिन दो साल बाद ही कैंसर से उनकी मौत हो गई। फिर के. करूणानिधि पार्टी के नए नेता बने। इसके बाद डीएमके में झगड़े शुरू हो गए। पार्टी के एक और नेता और लोकप्रिय अभिनेता एमजी. रामचंद्रन ने पार्टी के हिसाब-किताब में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा तो डीएमके नेतृत्व ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। 1972 में एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) ने अपनी नई पार्टी एआईएडीएमके (आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषघम) बनाई। इस पार्टी की विचारधारा भी वही थी, जो डीएमके की थी। लेकिन इस पार्टी का नेतृत्व उच्च जाति के द्रविड़ियनों के हाथ में था। एमजीआर खुद ऊंची जाति मलयाली नायर जाति से थे। जबकि उनकी राजनीतिक शिष्या और बाद में मुख्यमंत्री बनी जयललिता ब्राह्मण थीं। जबकि डीएमके की अगुवाई मोटे तौर पर ओबीसी और दलित नेता करते रहे हैं। इस मायने में एआईएडीमके को डीएमके की तुलना में 'सॉफ्ट द्रविड पॉलिटिक्स' करने वाली अथवा आस्तिक सेक्युलरवादी पार्टी माना जा सकता है। तमिलनाडु में बीते पचास सालों तक इन्हीं दो पार्टियों के बीच सत्ता की अदला- बदली होती रही है। उसका मुख्य कारण रेवड़ी वितरण और एंटी इनकम्बेंसी रहा है। तमिलनाडु की तीन पीढ़ियां इसी माहौल में पली-बढ़ी हैं। लेकिन जेन जी के जमाने में अब पहली बार बेहतर रोजगार, जीवन शैली, बाकी देश और दुनिया से जुड़ने की आकांक्षा और नई राजनीति की तलाश के आग्रह ने द्रविड़ राजनीति के घेरे को तोड़ा है। खुद विजय की पार्टी की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसे सुशासन और बड़ी रेवड़ियां बांटने का वादा करने वाली पार्टी माना जा सकता है। हालांकि विजय द्रविड़ आंदोलन के मूल तत्वों से एकदम अलग तो नहीं जा सकते, लेकिन उसे ज्यादा समावेशी बनाने के आग्रह के साथ काम जरूर कर सकते हैं। उन्हें तो अभी अपना संगठन भी खड़ा करना है।

तो क्या तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन का जोश अब उतार पर है? सीमित अर्थ में इसका जवाब 'हां' में हो सकता है। इसका बड़ा कारण तो यह है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा निशाने पर रही और कुल आबादी का महज 2.5 फीसदी ब्राह्मण जाति राजनीतिक रूप से पूरी तरह हाशिए पर हैं। बहुत से ब्राह्मणों ने तो तमिलनाडु छोड़कर अन्यत्र अपने आशियाने बसा लिए हैं। ज्यादातर पार्टियां उन्हें टिकट भी नहीं देतीं। दूसरे, राज्य की सत्ता अब मोटे तौर पर पिछड़ी जातियों के हाथ में आ गई है। तीसरे, तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों में 69 प्रतिशत आरक्षण 1969 में ही लागू हो गया था। जिसकी वजह से जातियों को अवसर की समानता का लक्ष्य काफी हद तक पूरा हो चुका है। ऐसे में आज बड़े पैमाने पर सभी जातियों के युवा तीव्र जातीय विभेद और दलित सिंड्रोम से बाहर निकल कर खुद को राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने लगे हैं। यही कारण है कि वहां मतदाताओं ने इस बार द्रविड राजनीति के विकल्प के रूप में थलपति विजय की पार्टी को चुना। हालांकि घोर जातिवादी तत्व विजय के उदय को पचा नहीं पा रहे हैं।

लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि तमिलनाडु अब द्रविड राजनीति से मुक्त हो गया है। इस चुनाव में द्रविड राजनीति के पुरोधा दोनों दलों का कुल वोट अभी भी 55.40 फीसदी है। भले ही वो दो पार्टियों में बंटा हो। अगर विजय की पार्टी को 'सेकुलर' मान लें तो उसे 34.92 प्रतिशत वोट मिला है, जो द्रविड़ राजनीति के समर्थकों की तुलना में काफी कम है। बावजूद इसके अगर कांग्रेस जैसी खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां द्रविड़वादी डीएमके का पल्ला छोड़ टीवीके से जुड़ने की इच्छुक हैं तो इसके पीछे कारण यही है कि वो राज्य में तीसरी ताकत के रूप में अपने उभार की भी संभावनाएं देख रही है। चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस चुनाव पूर्व ही टीवीके से गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उसे रूकवा दिया।

उधर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली और द्रविड़ राजनीति के बीच एआईएडीमके के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल भाजपा भी विजय के उदय से मन ही मन खुश है। भाजपा ने भी चुनाव के पूर्व विजय की पार्टी से तालमेल की कोशिशें की थीं, लेकिन विजय ने ही साम्प्रदायिक ताकतों से मेल के कारण संभावित राजनीतिक नुकसान की आशंका के चलते हाथ आगे नहीं बढ़ाया। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु में भारी जीत के बाद विजय को बधाई देने के लिए खुद फोन किया। इसमें भी कई संकेत छिपे हैं। अब देखना यह है कि विजय किसका समर्थन लेते हैं। छोटी सेक्युलर पार्टियों का या फिर किसी द्रविड़वादी पार्टी का? तमिलनाडु में पूर्व में सत्तारूढ़ डीएमके ने तो खुलकर केन्द्र से टकराव का रास्ता अपनाया था। उसने सनातनी हिंदुत्व, हिंदी और भाजपा के खिलाफ खुली वैचारिक जंग छेड़ दी थी। जिसे चुनाव में तमिलनाडु की जनता ने ही खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री के रूप में एम.के.स्टालिन का हार जाना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

अब सवाल यह है कि थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवीके किस रास्ते पर चलेगी? थलपति ने चुनाव प्रचार के दौरान डीएमके को कुचल देने की कसम खाई थी, क्योंकि डीएमके ने उनकी पार्टी की भ्रूण हत्या करने की कोशिश की थी। इसका अर्थ है कि वो कट्टर द्रविड़वाद से अलग लाइन पर चलेंगे। यही नहीं विजय को यह भी शक है कि उनकी हिंदू पत्नी द्वारा उनसे अलग होकर तलाक की अर्जी लगाने के पीछे भी डीएमके की ही चाल थी। विजय स्वयं कैथोलिक ईसाई हैं, लेकिन उनकी मां हिंदू हैं। उनकी मां ने धर्म नहीं बदला है और वो साईंबाबा की भक्त बताई जाती हैं। ऐसे में विजय खुद को दोनो धर्मों के प्रति सदभाव का रूख अपना सकते है। विजय की मूल जाति क्या है, इस बारे में कहा जाता है कि उनके पूर्वज तमिलनाडु के प्रभावशाली वेलल्लार समुदाय से थे, जो ऊंची जाति में ही गिनी जाती है।

यहां गौरतलब बात यह है कि आज तमिलनाडु में सभी प्रमुख पार्टियों का नेतृत्व ओबीसी नेताओं के हाथ में है, फिर चाहे वो डीएमके हो या एआईएडीएमके। जबकि कांग्रेस का नेतृत्व एक दलित नेता के. सेल्वापेरूथंगई कर रहे हैं। विजय राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, जो ईसाई हैं और जो प्रकारांतर से ऊंची जाति से आते हैं। राज्य में उनकी व्यापक स्वीकार्यता को उदार धार्मिक व जातीय दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। विजय अगर राजनीति में समावेशी मध्यमार्ग चुनते हैं तो इससे कट्टर द्रविड राजनीति कमजोर पड़ सकती है। जिससे भविष्य में भाजपा और कुछ हद तक कांग्रेस के नए सिरे से उभार की जमीन तैयार हो सकती है। इसे कट्टर द्रविड़वाद,नास्तिक सेकुलरवाद,आस्तिक सेकुलरवाद,हिंदुत्व के क्रमिक रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि यह कोई तुरंत होने की संभावना नहीं है। क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा को तमिलनाडु में केवल 1 सीट मिली है। अलबत्ता पिछले विस चुनाव की तुलना में उसका वोट शेयर महज 0.35 फीसदी बढ़ा, लेकिन सीटें 4 से घटकर 1 रह गई।

एक मायने में विजय द्रविड़ पार्टियों को ही फॉलो करेंगे और वो है रेवड़ी कल्चर। बल्कि वो इस मामले में उनसे भी एक कदम आगे जाते दिख रहे हैं, जिसका सीधा असर राज्य के खजाने पर पड़ेगा। विजय के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राज्य को 1 लाख करोड़ रू. की जरूरत होगी। विजय इस पर कैसे 'विजय' पाते हैं, यह देखना होगा।

विश्व रेडक्रॉस दिवस पर प्रदान किए 'सेवा सम्मान'

रेडक्रॉस के उद्देश्य और सेवा कार्यों से जन-जन को करें प्रेरित : राज्यपाल

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि दीन-दुखियों की सेवा, ईश्वर की सेवा का सशक्त माध्यम है। मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ग़रीब, वंचित और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करते रहे। उन्होंने कहा कि सेवा का दायरा बहुत विस्तृत है। रेडक्रॉस सदस्य दूरस्थ, ग्रामीण इलाकों जाकर जरूरतमंदों से मिले, उनकी समस्याओं को करीब से देखें, समझे और यथा संभव समाधान के आत्मीय प्रयास करें। हर सदस्य कम से कम 5 व्यक्तियों को रेडक्रॉस से जोड़े। राज्यपाल श्री पटेल ने रेडक्रॉस के सिद्धांतों, उद्देश्यों और कार्यों से जन-जन को प्रेरित करने का आह्वान किया। पीड़ित मानवता के प्रति रेडक्रॉस के संवेदनशील समर्पण से प्रेरणा लेने, वंचितों के उत्थान में सहभागी बनने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की युवाओं से अपील की। राज्यपाल श्री पटेल शुक्रवार को विश्व रेडक्रॉस दिवस पर आयोजित 'सेवा सम्मान समारोह' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रेडक्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यू-नॉट के जन्म दिवस पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समर्पित कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और समाज सेवी संस्थाओं को सम्मानित किया। मानवता की सेवा कार्यों और प्रयासों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सभी सम्मानित जनों को सम्पूर्ण समाज के सच्चे नायक और प्रेरणा स्रोत बताया। मध्यप्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (मेपकास्ट) परिसर में किया गया।

रेडक्रॉस की सीख कर्मों में भी झलकनी चाहिए

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विश्व रेडक्रॉस दिवस, मात्र एक दिवस का उत्सव नहीं, बल्कि मानवता, सेवा, करुणा और समर्पण की निरंतर प्रवाहित धारा का स्मरण है। युद्ध के मैदान में पीड़ा देख कर लिया गया संकल्प, आज पीड़ित मानवता की सेवा का वैश्विक आंदोलन बन गया है, जो हमें बताता है कि 'सेवा ही सर्वोच्च धर्म है।' उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के 7 मूल सिद्धांत- मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सर्व व्यापकता, जीवन जीने के सच्चे मार्गदर्शक हैं। इनका मन, वचन और कर्म से 365 दिन पालन ही, समावेशी समाज निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने का प्रभावी तरीका है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि रेडक्रॉस की सीख, शब्दों तक सीमित नहीं हो, यह हमारे कर्मों में भी झलकनी चाहिए। इसके लिए समाज को और अधिक संवेदनशील बनाना होगा। सम्मानित लोग, रेडक्रॉस के कार्यों में अपनी निष्ठा, समर्पण, सेवा-भाव के संस्कारों से भावी पीढ़ी को नेतृत्व प्रदान कर प्रोत्साहित करें। मानवता की सेवा के संकल्प के साथ पीड़ितों और वंचितों का दिल खोलकर सहयोग करें। मन, समय और संसाधनों से उनका साथ दें। समाज में पारस्परिक सहयोग तथा संवेदनशीलता की भावना को और अधिक सशक्त बनाएं।

जन औषधि योजना हर वर्ग के लिए वरदान

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जन-औषधि योजना, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अत्यंत संवेदनशील पहल है। यह योजना हर वर्ग के लिए वरदान है। उन्होंने इस अभूतपूर्व योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति आभार जताया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश रेडक्रॉस सोसायटी दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक जन-औषधि केन्द्र खोलने के प्रयास करें। इस पहल से स्थानीय युवाओं को जोड़े। उन्हें जन-औषधि केन्द्र में उपलब्ध दवाओं, गुणवत्ता और कीमतों की जानकारी दें। राज्यपाल श्री पटेल का समारोह में मध्यप्रदेश रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन डॉ. श्याम सिंह कुमरे और वाइस चेयरमैन श्री मनीष रावल ने शॉल एवं श्रीफल से अभिनंदन किया। चेयरमैन डॉ. कुमरे ने स्वागत उद्बोधन दिया। मध्यप्रदेश रेडक्रॉस सोसायटी के कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई। आभार जनरल सेक्रेटरी श्री रामेन्द्र सिंह ने माना। कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर श्रीमती संस्कृति जैन, मेपकास्ट के महानिदेशक डॉ. अमित कोठारी, डॉ. ब्रिजेश श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश रेडक्रॉस सोसायटी की राज्य और जिला इकाई के पदाधिकारी, रेडक्रॉस सदस्य, स्वयंसेवक, सम्मान प्राप्तकर्ता और उनके परिजन उपस्थित थे।

डॉ. भार्गव 'भारत प्रतिभा सम्मान' से नई दिल्ली में सम्मानित किए गए

श्रेष्ठ कार्य निष्पादन और असाधारण योगदान के लिए सम्मानित

नई दिल्ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, रीवा और शहडोल संभाग के पूर्व कमिश्नर और लेखक डॉ. अशोक भार्गव को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में आयोजित समारोह में 'भारत प्रतिभा सम्मान' से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, विख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना पद्मविभूषण डॉ सोनल मानसिंह और विशेष अतिथि इंडियन लीगल एड सेंटर के चेयरमैन एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. प्रदीप राय द्वारा अलंकृत किया गया।

डॉ. भार्गव को यह सम्मान लोक प्रशासन, सामाजिक कल्याण, शिक्षा में गुणात्मक बदलाव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों, निर्वाचन प्रक्रिया में नवाचार, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं, कोविड -19 नियंत्रण में परिणामोन्मुखी प्रबंधकीय कौशल की दक्षता और साहित्यिक गतिविधियों आदि के क्षेत्र में किए गए उच्चतम कोटि के कार्य निष्पादन और असाधारण योगदान के लिए प्रदत्त किया गया है।

पूर्व में भी डॉ. अशोक भार्गव सर्वोत्तम निर्वाचन प्रक्रिया अपनाने तथा निर्वाचन में नवाचार के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नेशनल अवार्ड से, भारत की जनगणना में असाधारण कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रपति पदक से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 'प्राइड ऑफ़ एमपी' अवार्ड और 'मालव गौरव सम्मान' से तीन मर्तबा नेशनल स्कॉच अवार्ड, तीन राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के साथ ही अनेक प्रतिष्ठापूर्ण राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महत्व के इस सम्मान के लिए देश भर से 5 हजार से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। परिषद सचिवालय द्वारा प्रारंभिक जांच के आधार पर राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण, राष्ट्रीय ज्यूरी की समीक्षा की अनुशंसा के बाद भारत प्रतिभा सम्मान परिषद ने 14 श्रेणियों में विजेताओं की अंतिम अनुमोदित सूची में डॉ.अशोक कुमार भार्गव 'भारत प्रतिभा सम्मान' के लिए प्रथम स्थान पर नामांकित किया।

अब बहुत हुआ, आदेश का पालन करें

सुप्रीम कोर्ट बोला-मंत्री शाह को ऐसे कमेंट्स की आदत

भोपाल। सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन स्वीकृति देने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कड़े शब्दों में कहा- बस बहुत हुआ, अब हमारे आदेश का पालन कीजिए। सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि शायद उनके बयान को गलत समझा गया और वे महिला अधिकारी की प्रशंसा करना चाहते थे तो सीजेआई सूर्यकांत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा- यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। एक राजनेता के तौर पर उन्हें अच्छी तरह पता है कि किसी महिला अधिकारी की प्रशंसा कैसे की जाती है। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि मंत्री को इस तरह के कमेंट करने की आदत है।

इंदौर के पास रायकुंडा गांव में दिया था विवाद बयान- यह विवाद पिछले साल भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ की गई क्रॉस-बॉर्डर सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन की मीडिया ब्रीफिंग की थी। इसके बाद महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कहा था, ÷जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा किया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी ही एक बहन को भेजा। इस बयान को कर्नल कुरैशी के धर्म से जोड़कर देखा गया, जिसकी हर तरफ निंदा हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।

भोपाल में निगम ने प्रशासन से मांगी जमीन,अब कैम्पस में ही बनाने पर मंथन

73 करोड़ की नई बिल्डिंग...पर परिषद मीटिंग हॉल नहीं बनाया

भोपाल। भोपाल में नगर निगम की नई बिल्डिंग पर कुल 73 करोड़ रुपए खर्च हुए। इनमें बिल्डिंग के सिविल वर्क से लेकर उसके इंटीरियर समेत अन्य काम भी शामिल हैं। इतनी भारी भरकम राशि खर्च होने के बावजूद जिम्मेदार परिषद का मीटिंग हॉल बनाना भूल गए। इसके लिए जिला प्रशासन से 5 एकड़ जमीन भी मांगी गई, लेकिन गुरुवार को लोकार्पण में संकेत मिले कि नई जमीन की जगह निगम परिषद का हॉल कैम्पस में ही बनेगा। लोकार्पण कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए महापौर मालती राय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से 5 एकड़ जमीन की मांग की थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और निगम कमिश्नर संस्कृति जैन से बात भी की। सूत्रों के अनुसार, अतिरिक्त जमीन की बजाय बिल्डिंग के ठीक सामने परिसर में ही नया परिषद मीटिंग हॉल बनाने की बात सामने आई है। यदि ऐसा होता है तो पार्किंग की जगह नया मीटिंग हॉल बन सकता है। ताकि, भविष्य में परिषद की बैठकें यहां हो सकें।

43 से 73 करोड़ रुपए पहुंची बिल्डिंग की लागत

दूसरी ओर, जिस बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया है, पहले उसकी लागत 43 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन गुरुवार को जब इसका उद्घाटन हुआ तो इसकी लागत 73 करोड़ रुपए बताई गई। 43 करोड़ रुपए में सिविल के काम हुए, जबकि बाकी राशि से अन्य कार्य करवाए गए। बता दें कि यह प्रदेश की पहली नगरीय निकाय बिल्डिंग है, जो जियोथर्मल तकनीक से लैस है। पार्किंग पर लगे सोलर पैनलों से 300 किलोवाट बिजली बनेगी। नवनिर्मित मुख्यालय का नाम 'अटल भवन' रखा गया है। इसके लोकार्पण के साथ नीमच जिले में भोपाल निगम द्वारा स्थापित 10.5 मेगावॉट सोलर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया गया।

भोपाल में तलाकशुदा महिला से परिचित ने किया रेप

शादी करने से इनकार किया तब थाने पहुंची पीड़िता, एफआईआर दर्ज

भोपाल। भोपाल के कमला नगर इलाके में एक तलाकशुदा महिला से युवक ने करीब पांच साल रेप किया। आरोपी ने पीड़िता को शादी करने का भरोसा दिलाया था। अब युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया है। तब पीड़िता ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। टीआई निरूपमा पांडे के मुताबिक 31 वर्षीय युवती थाना क्षेत्र में रहती है। 2021 में उसके मोबाइल पर रॉग नंबर से कॉल आया था। इसके बाद दोनों के बातचीत होने लगी और मामला प्रेम प्रसंग तक पहुंच गया। इस दौरान आरोपी युवक ने अपना नाम सुरेंद्र राय बताया और मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। जहां आरोपी युवक ने उसे बताया कि वह तलाकशुदा है और वह उससे शादी करना चाहता। उसके बाद से वह लगातार पीड़िता का शोषण कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले आरोपी युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया। उसकी करतूतों से परेशान होकर गुरुवार को पीड़िता थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। आरोपी युवक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।